घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 188- रविवार 10 - मई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

सुवेंदु बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने

शुवेंदु अधिकारी संग पांच मंत्रियों ने ली शपथ

कोलकाता,09 मई 2026। सुवेंदु अधिकारी शनिवार को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। सुवेंदु ने बांग्ला में ईश्वर के नाम की शपथ ली। शपथ के बाद सुवेंदु, पीएम के पास गए और उन्हें झुककर प्रणाम किया। बंगाल के गवर्नर आरएन रवि ने सुवेंदु के अलावा 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया,क्षुदीराम टूडू और निषिथ प्रमाणिक शामिल रहे। शपथ में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले मोदी ने मंच पर रवींद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीएम ने भाजपा के 98 साल के कार्यकर्ता माखनलाल सरकार का सम्मान किया। मंच पर आते ही प्रधानमंत्री सीधे सरकार के पास गए, उन्हें शॉल ओढ़ाया और फिर उनके पैर छुए।

पीएम मोदी का घुटनों के बल बैठकर जनता को प्रणाम

सुवेंदु के पिता बोले...आज आम लोगों को भी जीत मिली

जैसे ही सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, उनके पिता शिशिर कुमार अधिकारी ने कहा, 'हमने नंदीग्राम की लड़ाई लड़ी और उस संघर्ष की अगुआई सुवेंदु ने की थी। बार-बार,अलग-अलग तरीकों से उन्हें पीछे धकेलने की कोशिशें की गईं,लेकिन आज आम लोगों को भी जीत मिली है। यह सिर्फ नंदीग्राम की बात नहीं है,आज कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल की संस्कृति और भावना को पहचान मिली है। '

पश्चिम बंगाल अब विकास,सुरक्षा,समृद्धि के नए दौर की ओर अग्रसर : नितिन नबीन

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर सुवेंदु अधिकारी को सफल कार्यकाल की बधाई दी। उन्होंने कहा कि 'डबल इंजन सरकार' की शक्ति के साथ पश्चिम बंगाल अब विकास, सुरक्षा और समृद्धि के नए दौर की ओर अग्रसर है तथा 'सोनार बांग्ला' के साझा संकल्प को साकार करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। नितिन नबीन ने एक्स पर साझा किए बधाई संदेश में कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर सुवेंदु अधिकारी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

सुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए विष्णुदेव साय,बोले...'सोनार बांग्ला' का सपना होगा सच

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कोलकाता में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, जहाँ उन्होंने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले सुवेंदु अधिकारी को ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने बंगाल में सत्ता परिवर्तन को जनसंकल्प की जीत बताते हुए नए मंत्रिपरिषद के सफल कार्यकाल की कामना की। यह दौरा छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के बीच राजनैतिक और प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करेगा। 'डबल इंजन' की सरकार बनने से दोनों राज्यों के बीच विकास योजनाओं और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को नई गति मिलने की संभावना है, जिसका सीधा लाभ वहां रह रहे छत्तीसगढ़ी प्रवासियों को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोलकाता पहुँचकर सुवेंदु अधिकारी से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट कर शुभकामनाएं दीं। श्री साय ने कहा कि यह जनादेश केवल सरकार बदलने का नहीं है, बल्कि बंगाल में सुशासन, पारदर्शिता और नई कार्यसंस्कृति की स्थापना का प्रतीक है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब बंगाल विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। साय ने जोर देकर कहा कि नई सरकार के आने से बंगाल के युवाओं को रोजगार, किसानों को समृद्धि और मातृशक्ति को सुरक्षित वातावरण प्राप्त होगा। उन्होंने 'सोनार बांग्ला' की अवधारणा को साकार करने की दिशा में इस शपथ ग्रहण को एक निर्णायक कदम बताया।

छपते-छपते

एमसीबी में सरगुजा आईजी के दौरे का दिखा असर,2 दिन बाद जुए पर बड़ी कार्रवाई

मनेन्द्रगढ,09 मई 2026(घटती-घटना)। मनेन्द्रगढ़ में पुलिस ने जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है, कार्रवाई के दौरान बैकुंठपुर के एक चर्चित पार्षद भी पुलिस गिरफ्त में आए, जिन्हें लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार संबंधित पार्षद को भविष्य में नपा अध्यक्ष पद का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन जुए की कार्रवाई में नाम सामने आने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है, बताया जा रहा है कि सरगुजा आईजी के हालिया दौरे के बाद पुलिस लगातार एक्शन मोड में है और अवैध गतिविधियों पर सख्ती बढ़ाई गई है, मनेन्द्रगढ़ की इस कार्रवाई को भी उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है, अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में जिलेभर में ऐसे और बड़े एक्शन देखने को मिलेंगे?

पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार,ईडी की छापामारी के बाद अरेस्ट

चंडीगढ़,09 मई 2026। पंजाब के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ स्थित उनके सरकारी आवास पर शनिवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप लगाया है। सूत्रों के अनुसार, ईडी की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग, फेमा उल्लंघन, जमीन से जुड़े मामलों और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जांच से जुड़ी हुई है। एजेंसी सिर्फ चंडीगढ़ तक सीमित नहीं रही, बल्कि लुधियाना, जालंधर और गुरुग्राम समेत कई शहरों में भी छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि जांच के दायरे में संजीव अरोड़ा के परिवार और उनकी कंपनी से जुड़े कुछ दफ्तर भी शामिल हैं। मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से बयानबाजी से शुरू हो गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। मान ने कहा कि पिछले एक साल में यह तीसरी बार है जब ईडी संजीव अरोड़ा के घर पहुंची है, लेकिन एजेंसी को अब तक कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पंजाब गुरुओं और शहीदों की धरती है, जिसे दबाया नहीं जा सकता। भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए कर रही है।

एक्टर विजय तमिलनाडु के 9वें सीएम बनेंगे

राज्यपाल को 121 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा,शपथ समारोह आज सुबह 10 बजे...

चेन्नई,09 मई 2026। विजय ने शनिवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से लोकभवन में मुलाकात की और सरकार बनाने के लिए 121 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। बहुमत साबित करने के लिए 118 विधायकों की जरूरत थी। 4 मई को आए चुनाव परिणाम में विजय की पार्टी को सबसे ज्यादा 108 सीटें मिली थीं। लेकिन यह बहुमत से 10 कम थीं। टीवीके को कांग्रेस के 5,सीपीआई और सीपीआई(एम) के 2-2 विधायकों का समर्थन 8 मई तक मिल चुका था। शनिवार को वीसीके और आईयूएमएल ने टीवीके को अपने 2-2 विधायकों का समर्थन दिया। इधर, महाबलीपुरम स्थित फोर पॉइंट्स रिसॉर्ट के बाहर भारी सुरक्षा तैनात की गई है।

राज्यपाल ने विजय को सरकार बनाने का न्योता दिया

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने टीवीके चीफ विजय को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सरकार बनाने का न्योता दिया है। राज्यपाल ने विजय को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हुए 13 मई 2026 तक विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का निर्देश दिया है। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 10 मई को सुबह 10 बजे चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा। राज्यपाल आर्लेकर ने विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया है। चेन्नई स्थित लोकभवन में राज्यपाल ने विजय को नियुक्ति पत्र सौंपा।

बैंक धोखाधड़ी : मुंबई में अनिल अंबानी समूह के 17 ठिकानों पर सीबीआई का छापा

नई दिल्ली,09 मई 20526। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अनिल अंबानी समूह से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी मामलों में शनिवार को मुंबई में 17 स्थानों पर व्यापक छापेमारी की। यह कार्रवाई रिलायंस एडीए समूह की कंपनियों रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड तथा उनके निदेशकों के खिलाफ दर्ज मामलों में की गई। सीबीआई के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और भारतीय जीवन बीमा निगम को हजारों करोड़ रुपये के कथित नुकसान से जुड़े मामलों की जांच जारी है। यह छापेमारी 08 मई को मुंबई स्थित सीबीआई मामलों की विशेष अदालत द्वारा जारी तलाशी वारंट के आधार पर की गई। जांच एजेंसी ने निदेशकों के आवासीय परिसरों के अलावा उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी तलाशी ली, जिनके खातों का कथित तौर पर बैंक धनराशि के डायवर्जन और लेन-देन के लिए उपयोग किया गया था। एजेंसी ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान कई महत्वपूर्ण और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि कई मध्यस्थ कंपनियां एक ही पते से संचालित हो रही थीं, जिससे लेन-देन के नेटवर्क और धनराशि के उपयोग को लेकर संदेह और गहरा हुआ है।

मातम में बदली खुशियां : दुल्हन के स्वागत में चली गोली,हर्ष फायरिंग में दूल्हे के चाचा की मौत

झांसी,09 मई 2026। उत्तर प्रदेश के झांसी में शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं जब दुल्हन के आने की खुशी में की गई हर्ष फायरिंग एक व्यक्ति की मौत का कारण बन गई। यह घटना बड़ागांव थाना क्षेत्र के ग्राम डिमरौनी की है, जहां शादी के बाद दूल्हा-दुल्हन के घर पहुंचने पर डीजे बज रहा था और परिजन नाच-गाकर जश्न मना रहे थे। इसी दौरान चली गोली दूल्हे के चाचा को लग गई, जिससे पूरे समारोह में अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार, दुल्हन की विदाई के बाद शुक्रवार शाम करीब 5 बजे नवविवाहित जोड़ा घर पहुंचा था। उनके स्वागत में घर के बाहर डीजे बज रहा था और परिवार व ग्रामीण खुशी में झूम रहे थे। इसी दौरान मौजूद लोगों के बीच अचानक हर्ष फायरिंग शुरू हो गई। गोली लगते ही खुशियों का माहौल चीख-पुकार में बदल गया और परिजन घायल को तुरंत अस्पताल लेकर भागे। मृतक की पहचान करीब 50 वर्षीय महेश यादव पुत्र हरिसिंह यादव के रूप में हुई है। वह ढिमरौनी गांव का रहने वाला था और खेती-किसानी करता था। उसके परिवार में दो बेटियां और एक बेटा है। बड़ी बेटी पूजा की शादी हो चुकी है, जबकि बेटा विक्रम (19) और बेटी मुस्कान अविवाहित हैं।

योगी मंत्रिमंडल में आज 6 नए मंत्री बनेंगे

आज राजभवन में होगा शपथ ग्रहण, सीएम ने राज्यपाल को लिस्ट सौंपी

लखनऊ,09 मई 2026। योगी कैबिनेट का रविवार को दूसरी बार विस्तार होगा। आज दोपहर 3 बजे 5-6 नए मंत्री शपथ लेंगे। सीएम योगी शनिवार शाम करीब साढ़े 6 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुंचे। योगी ने राज्यपाल को नए बनने वाले मंत्रियों की लिस्ट सौंपी। कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। अगर ऐसा होता है, तो रविवार को शपथ लेने वाले मंत्रियों की संख्या बढ़ भी सकती है। सपा से बगावत करने वाले विधायक मनोज पांडेय का नाम फाइनल हो चुका है। पूजा पाल का भी मंत्री बनना लगभग तय है। इनके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, सुरेंद्र दिलेर और कृष्णा पासवान के नाम पर भी मुहर लग चुकी है। नाई समाज से एमएलसी रामचंद्र प्रधान, विश्वकर्मा समाज से वाराणसी के भाजपा एमएलएसी हंसराज विश्वकर्मा को मंत्री बनाया जा सकता है। ब्राह्मण समाज से पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा, भाजपा के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला भी मंत्री पद की दौड़ में हैं। अभी सीएम योगी को मिलाकर कुल 54 मंत्री हैं। इस तरह 6 मंत्री और बन सकते हैं। योगी 2.0 का पहला विस्तार लोकसभा चुनाव- 2024 से ठीक पहले 5 मार्च, 2024 को हुआ था।

मनोज पांडेय | श्रीकांत शर्मा | भूपेंद्र सिंह चौधरी

ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्रोफाइल बदला :पूर्व सीएम की जगह 15वीं, 16वीं,17वीं विधानसभा का सीएम और तृणमूल कांग्रेस का फाउंडर लिखा

कोलकाता,09 मई 2026। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जारी बदलावों के बीच तृणमूल कांग्रेस प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल अपडेट किया है। वहीं, शपथ ग्रहण के बाद शुभेंदु अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में अपने नाम के साथ मुख्यमंत्री शब्द जोड़ लिया। सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर ममता बनर्जी ने अब अपने प्रोफाइल में खुद को तीन बार की मुख्यमंत्री बताया है। उन्होंने लिखा है कि वह 15वीं, 16वीं और 17वीं विधानसभा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही हैं और फिलहाल, तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। लेकिन उन्होंने कहीं भी 'पूर्व मुख्यमंत्री' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। अब तक उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स में 'मुख्यमंत्री' लिखा हुआ था, लेकिन हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के बाद यह बदलाव सामने आया है। चुनाव परिणाम आने के बाद तृणमूल कांग्रेस की ओर से दावा किया गया था कि पार्टी पराजित नहीं हुई बल्कि उसे साजिश के तहत हराया गया है।

संपादकीय

सरकार और देश में अंतर करना आवश्यक

इ लोकतंत्र की सबसे बुनियादी सच्चाइयों में से एक यह है कि देश और सरकार एक ही इकाई नहीं होते। यह फर्क केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक स्वास्थ्य का मूल आधार है। देश एक जीवंत, बहुस्तरीय और निरंतर विकसित होने वाली सामूहिक चेतना है और उसकी विविधताओं,संघर्षों, इतिहास,आकांक्षाओं और भविष्य का समुच्चय होता है। इसके विपरीत,सरकार एक अस्थायी व्यवस्था है,जिसे जनता समय-समय पर चुनती है। सरकारें आती-जाती रहती हैं, पर देश बना रहता है। इस सरल-सी प्रतीत होने वाली सच्चाई को धुंधला करना,लोकतंत्र के आत्मा को कमजोर करना है।

समस्या तब उत्पन्न होती है,जब सत्ताधारी दल अपने राजनीतिक हितों को राष्ट्रहित के रूप में प्रस्तुत करने लगता है। यह प्रवृत्ति नई नहीं है, लेकिन आज के दौर में इसका स्वर अधिक मुखर और आक्रामक हो गया है। सरकार की आलोचना को देश की आलोचना के रूप में चित्रित करना,असहमति को राष्ट्रद्रोह के साथ जोड़ देना और किसी एक नेता की छवि को राष्ट्र की गरिमा के साथ मिला देना,ये सभी प्रवृत्तियां लोकतांत्रिक विमर्श को सीमित करती है। इससे नागरिकों पर दबाव पैदा होता है कि वे सवाल उठाने से बचें, अन्यथा उन्हें देश-विरोधी ठहरा दिया जाएगा।

यह माहौल लोकतंत्र की मूल भावना-स्वतंत्र विचार और बहस के सर्वथा प्रतिकूल है। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में आलोचना केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि नागरिकों का कर्तव्य भी होती है। सरकार की नीतियों,निर्णयों और कार्यशैली पर सवाल उठाना,उनका विश्लेषण करना और आवश्यकतानुसार उनका विरोध करना सक्रिय नागरिकता के अनिवार्य तत्व हैं। यदि यह प्रक्रिया कमजोर पड़ती है, तो सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ता है और जवाबदेही कम होती जाती है। जब-जब सरकार और राष्ट्र को एक मान लिया गया,तब-तब लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुईं,नागरिक अधिकारों पर आघात हुआ और तानाशाही प्रवृत्तियां पनपीं।

किसी भी उच्च पदस्थ नेता की गरिमा और प्रतिष्ठा निस्संदेह महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उसे राष्ट्र की गरिमा का पर्याय बना देना एक खतरनाक सरलीकरण है। राष्ट्र की प्रतिष्ठा किसी एक व्यक्ति की छवि पर नहीं,बल्कि उसके संस्थानों की मजबूती, नागरिकों की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की निष्पक्षता और समाज की समावेशी संरचना पर निर्भर करती है। जब हम किसी नेता की आलोचना को राष्ट्र के अपमान के रूप में देखने लगते हैं,तो हम अनजाने में लोकतंत्र के उस संतुलन को बिगाड़ देते हैं, जो संस्थाओं और व्यक्तियों के बीच स्थापित होना चाहिए। यह याद रखना प्रासंगिक है कि लोकतंत्र में संस्थाएं व्यक्तियों से बड़ी होती हैं।

व्यक्ति-पूजा का यह चलन धीरे-धीरे संस्थागत ढांचे को कमजोर करता है और लोकतंत्र को एक व्यक्ति-केंद्रित व्यवस्था में बदलने का खतरा पैदा करता है। सत्ताधारी दल का हित और राष्ट्रहित हमेशा एक जैसे नहीं होते। हर दल स्वाभाविक रूप से अपने विस्तार,प्रभाव और चुनावी सफलता के लिए काम करता है और यह लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा है,लेकिन जब इन हितों को राष्ट्रहित के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और विरोध की आवाजों को दबाने का प्रयास होता है, तब समस्या पैदा होती है। इससे नीति-निर्माण में विविध दृष्टिकोणों की गुंजाइश कम हो जाती है और निर्णय एकतरफा हो सकते हैं।

लोकतंत्र का सार ही यह है कि विभिन्न विचारों के बीच संवाद हो और उसी से नीतियों का निर्माण हो। इस बहस में सबसे केंद्रीय भूमिका नागरिक की है। लोकतंत्र में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। सवाल पूछना,जानकारी जुटाना,नीतियों का मूल्यांकन करना और अपनी स्वतंत्र राय बनाना,ये सभी लोकतांत्रिक नागरिकता के आवश्यक तत्व हैं। यदि नागरिक इस जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं,तो सत्ता का असंतुलन बढ़ता है और लोकतंत्र कमजोर पड़ने लगता है। यह भी समझना जरूरी है कि आलोचना का अर्थ विरोध या नकारात्मकता नहीं होता। रचनात्मक आलोचना वह प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से नीतियों में सुधार होता है और शासन अधिक प्रभावी बनता है।

गटर में उतरती इंसानियत

सफाईकर्मियों की मौतें बताती हैं कि जातिवाद आज भी जिंदा है...

प्रियंका सौरभ
हिसार,हरियाणा

भा भारत के शहर आज दो तस्वीरों में बँटे हुए दिखाई देते हैं। एक तस्वीर चमचमाती सड़कों,स्मार्ट सिटी योजनाओं,बड़े-बड़े मॉल और स्वच्छता अभियानों की है,जबकि दूसरी तस्वीर कूड़े के ढेरों,बदबूदार नालियों,उफनते सीवरों और उनमें उतरते इंसानों की है। दुर्भाग्य यह है कि दूसरी तस्वीर को देखने से समाज अक्सर बचता है, क्योंकि वह तस्वीर केवल गंदगी की नहीं,बल्कि हमारे सामाजिक चरित्र की सच्चाई भी दिखाती है। शहरों की सफाई जिन लोगों के भरोसे है,वही लोग आज भी सबसे अधिक अपमान,असुरक्षा और उपेक्षा झेल रहे हैं। यह केवल प्रशासनिक असफलता नहीं,बल्कि उस जातिवादी मानसिकता का परिणाम है जो हजारों वर्षों से कुछ लोगों को गंदगी साफ करने वाला मानती आई है।

यह विडंबना ही है कि जिस समाज में सफाई को ईश्वर के बराबर बताया जाता है,उसी समाज में सफाई करने वाले इंसान को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता। जिन हाथों से शहर साफ रहते हैं,उन्हीं हाथों को लोग अपने घरों की चौखट पर सम्मान नहीं देना चाहते। संविधान ने बराबरी का अधिकार दिया, कानूनों ने अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया,लेकिन समाज के दिमागों में बैठी जाति की गंदगी आज भी जस की तस मौजूद है। यही कारण है कि सफाई कर्मचारी आज भी अधिकांशतः एक ही जाति विशेष से आते हैं। आधुनिक भारत का यह सबसे बड़ा सामाजिक विरोधाभास है कि चाँद पर पहुँचने वाला देश आज भी अपने ही नागरिकों को नंगे हाथों से गटर साफ करने पर मजबूर करता है। हर वर्ष देश के अलग-अलग हिस्सों से खबर आती है कि सीवर साफ करते समय जहरीली गैस से कई सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। कुछ देर के लिए मीडिया में चर्चा होती है, प्रशासन दुख जताता है,नेता मुआवजे की घोषणा करते हैं और फिर मामला खत्म हो जाता है। लेकिन उन परिवारों के लिए जिंदगी कभी सामान्य नहीं होती। एक मजदूर की मौत केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं होती,बल्कि पूरे परिवार की उम्मीदों, बच्चों के भविष्य और घर की रोटी का अंत होती है। सबसे दुखद बात यह है कि इन मौतों को समाज ने लगभग सामान्य मान लिया है। जैसे यह कोई हादसा नहीं, बल्कि उनका तयशुदा भाग्य हो।

सवाल यह है कि आखिर क्यों आज भी इंसानों को सीवर में उतरना पड़ता है? क्या तकनीक के इस दौर में मशीनें यह काम नहीं कर सकतीं? सच यह है कि मशीनें मौजूद हैं,तकनीक मौजूद है, संसाधन भी मौजूद हैं,लेकिन सफाई कर्मचारियों की जान को कभी प्राथमिकता नहीं माना गया। गरीब मजदूर की जिंदगी इस व्यवस्था के लिए सस्ती है। यही कारण है कि सुरक्षा उपकरणों के बिना लोगों को जहरीले गटरों में उतार दिया जाता है। कई बार ठेकेदार और अधिकारी जानते हैं कि यह गैरकानूनी है,फिर भी यह सब जारी रहता है, क्योंकि मरने वाला कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं होता।

यदि किसी बड़े अधिकारी,डॉक्टर या सरकारी कर्मचारी की असामयिक मृत्यु होती है,तो पूरा तंत्र सक्रिय हो जाता है। परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है, सरकारी नौकरी मिलती है, नेताओं के संदेश आते हैं और संवेदनाएँ प्रकट की जाती हैं। ऐसा होना चाहिए,क्योंकि हर इंसान का जीवन मूल्यवान है। लेकिन वही संवेदनशीलता तब क्यों गायब हो जाती है जब कोई सफाई कर्मचारी सीवर में दम तोड़ देता है? उसकी पत्नी और बच्चों के आँसू कम कीमती क्यों माने जाते हैं? उसकी मौत पर समाज उतना विचलित क्यों नहीं होता? इसका उत्तर केवल आर्थिक या प्रशासनिक नहीं,बल्कि सामाजिक है। हमारे दिमागों में सदियों से भरी जातिवादी सोच ने सफाई कर्मचारियों की पीड़ा को सामान्य बना दिया है।

असल में सड़कों पर फैली गंदगी से ज्यादा खतरनाक गंदगी हमारे दिमागों में भरी हुई है। सड़क का कचरा नगर निगम उठा सकता है, लेकिन मानसिक कचरा पीढ़ियों की सोच बदलने से ही हटेगा। हमने सफाई को काम नहीं, जाति बना दिया। हमने कुछ लोगों को यह विश्वास दिलाया कि उनका जन्म ही गंदगी साफ करने के लिए हुआ है। यही सोच लोकतंत्र और मानवता दोनों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। किसी भी सभ्य समाज में कोई पेशा जन्म से तय नहीं होता, लेकिन भारत में जाति ने इंसान की पहचान, सम्मान और रोजगार तक तय कर दिए।

विडंबना यह भी है कि स्वच्छ भारत जैसे अभियान चलाने वाला देश सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाया। फोटो खिंचवाने के लिए झाड़ू पकड़ना आसान है,लेकिन सीवर में उतरते इंसानों की जिंदगी बदलने के लिए गंभीर राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए। आज भी अनेक नगर पालिकाओं में सीवर सफाई का पूरा काम ठेकेदारों के भरोसे चलता है। ठेकेदार लागत बचाने के लिए सुरक्षा उपकरण नहीं देते और मजदूर मजबूरी में मौत के कुएँ में उतर जाते हैं। जब हादसा होता है तो जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डाल दी जाती है। किसी अधिकारी या ठेकेदार को शायद ही कभी सख्त सजा मिलती हो। यही दंडहीनता इन मौतों को जारी रखती है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि सफाई कर्मचारियों के साथ केवल आर्थिक अन्याय नहीं,बल्कि सामाजिक अपमान भी जुड़ा हुआ है। वे शहरों की सफाई करते हैं, लेकिन अक्सर गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर होते हैं। उनके बच्चों को स्कूलों में भेदभाव झेलना पड़ता है। कई जगह आज भी लोग उनके साथ बैठकर खाना खाने से हिचकते हैं। यह कैसा समाज है जो सफाई तो चाहता है, लेकिन सफाई करने वाले इंसान को सम्मान नहीं देना चाहता?

हमें यह समझना होगा कि सफाई कोई छोटा काम नहीं है। डॉक्टर शरीर बचाता है,शिक्षक भविष्य बनाता है और सफाई कर्मचारी समाज को बीमारियों से बचाता है। यदि एक दिन सफाई कर्मचारी काम बंद कर दें,तो शहरों का जीवन ठहर जाएगा। महामारी फैल जाएगी,बदबू और संक्रमण लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे। फिर भी सबसे कम सम्मान और सबसे ज्यादा खतरा उसी पेशे से जुड़ा है। यह केवल सामाजिक विफलता नहीं, बल्कि नैतिक दिवालियापन भी है।

समस्या का समाधान केवल भाषणों से नहीं होगा। सबसे पहले सीवर और गटर सफाई का पूर्ण मशीनीकरण जरूरी है। किसी भी इंसान को जहरीली गैसों के बीच उतरने के लिए मजबूर करना सीधा-सीधा मानवाधिकारों का उल्लंघन है। सरकारों को आधुनिक मशीनों, रोबोटिक तकनीक और सुरक्षा उपकरणों पर गंभीर निवेश करना होगा। इसके साथ ही यदि किसी सफाई कर्मचारी की मौत होती है,तो संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों पर गैर-इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी,तब तक यह सिलसिला नहीं रुकेगा।

इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों के परिवारों को सम्मानजनक मुआवजा मिलना चाहिए। केवल कुछ लाख रुपये देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती। कम से कम एक करोड़ रुपये की सहायता,परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, बच्चों की शिक्षा और आवास की गारंटी दी जानी चाहिए। क्योंकि जिसने अपनी जान गंवाई,वह केवल मजदूर नहीं था, बल्कि समाज को स्वस्थ रखने वाली व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था।

लेकिन कानून और मुआवजा भी तब तक अधूरे रहेंगे जब तक समाज अपनी सोच नहीं बदलेगा। स्कूलों,विश्वविद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं को जातिवाद के खिलाफ गंभीर जागरूकता अभियान चलाने होंगे। बच्चों को यह सिखाना होगा कि कोई काम छोटा नहीं होता और किसी इंसान की गरिमा उसके पेशे से कम नहीं होती। जब तक सफाई कर्मचारियों को बराबरी का सम्मान नहीं मिलेगा,तब तक स्वच्छ भारत का सपना भी अधूरा रहेगा।

आज जरूरत केवल शहरों की सफाई की नहीं,बल्कि समाज की आत्मा को साफ करने की है। हमें अपने भीतर झाँककर पूछना होगा कि आखिर क्यों एक सफाई कर्मचारी की मौत हमें उतना विचलित नहीं करती जितना किसी बड़े अधिकारी की मौत करती है? क्यों आज भी जाति के आधार पर काम बँटे हुए हैं? और क्यों हम आधुनिकता का दावा करते हुए भी मानसिक रूप से सदियों पीछे खड़े हैं?

किसी भी राष्ट्र की असली पहचान उसकी ऊँची इमारतों,चौड़ी सड़कों और आर्थिक विकास से नहीं होती,बल्कि इस बात से होती है कि वह अपने सबसे कमजोर और मेहनतकश नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यदि आज भी सफाई कर्मचारी सीवरों में मर रहे हैं और समाज चुप है, तो यह केवल उनकी हार नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र की हार है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि असली गंदगी कूड़े के ढेरों में नहीं,बल्कि उस सोच में है जो इंसानों को जाति के आधार पर बाँटती है। जिस दिन यह मानसिक गंदगी साफ हो जाएगी, उसी दिन भारत सचमुच स्वच्छ,सभ्य और मानवीय राष्ट्र कहलाने के योग्य बनेगा।

महिला आरक्षण पर राजनीतिक दलों का दोहरा चरित्र

ललित गर्ग
पटपड़गंज,नई दिल्ली

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक यह है कि जिस देश में महिलाओं को शक्ति,मातृशक्ति और आधी दुनिया कहकर सम्मानित किया जाता है,वहीं राजनीति में उन्हें समान भागीदारी देने के प्रश्न पर लगभग सभी राजनीतिक दलों की नीयत संदिग्ध दिखाई देती है। संसद से लेकर चुनावी मंचों तक महिला आरक्षण के समर्थन में बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं,लेकिन जब उम्मीदवारों को टिकट देने का समय आता है,तब अधिकांश दल महिलाओं को हाशिये पर धकेल देते हैं। हालिया विधानसभा चुनावों ने इस विरोधाभास को एक बार फिर उजागर कर दिया है। पश्चिम बंगाल,तमिलनाडु,असम,केरल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को दिए गए टिकटों का आंकड़ा यह बताने के लिए पर्याप्त है कि महिला प्रतिनिधित्व को लेकर दलों की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर संसद में जोरदार राजनीतिक संघर्ष देखने को मिला, लेकिन उन्हीं दलों ने चुनावी मैदान में महिलाओं को पर्याप्त अवसर देने में उत्साह नहीं दिखाया। यह केवल राजनीतिक रणनीति नहीं,बल्कि लोकतांत्रिक नैतिकता का भी प्रश्न है।
सबसे अधिक चर्चा पश्चिम बंगाल चुनाव की रही। भारतीय जनता पार्टी ने 294 सीटों में से केवल लगभग 33 महिलाओं को टिकट दिए,जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 291 सीटों पर करीब 52 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया। यह संख्या कुल टिकटों का लगभग दस प्रतिशत ही बैठती है। तमिलनाडु में भी स्थिति बहुत अलग नहीं रही। सत्ता परिवर्तन के दावे करने वाले दलों ने महिलाओं को सीमित अवसर दिए। असम और केरल जैसे राज्यों में भी राजनीतिक दलों ने महिलाओं को प्रतीकात्मक उपस्थिति से आगे नहीं बढ़ने दिया। परिणाम यह हुआ कि कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों में महिलाओं की संख्या अत्यंत कम रही। यह स्थिति तब है, जब देश की लगभग आधी आबादी महिलाएं हैं। दरअसल भारतीय राजनीति लंबे समय से पुरुष प्रधान मानसिकता से संचालित होती रही है। राजनीतिक दल महिलाओं को अक्सर सुरक्षित या कमजोर उम्मीदवार मानते हैं। उन्हें यह भय रहता है कि महिला प्रत्याशी चुनावी संघर्ष,धनबल, बाहुबल और जातीय समीकरणों के बीच प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर पाएंगी। यही कारण है कि अधिकांश दल महिलाओं को उन्हीं सीटों पर टिकट देते हैं जहां उनकी जीत की संभावना कम होती है या जहां केवल प्रतीकात्मक उपस्थिति दर्ज करानी होती है।

विडंबना यह भी है कि जो राजनीतिक दल संसद में महिला आरक्षण के पक्ष में जोरदार भाषण देते हैं,वे अपने संगठनात्मक ढांचे में भी महिलाओं को निर्णायक स्थान देने से बचते हैं। अधिकांश राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के शीर्ष नेतृत्व पर पुरुषों का वर्चस्व है। महिलाओं को प्रायः महिला मोर्चा, सांस्कृतिक कार्यक्रम या सामाजिक अभियानों तक सीमित कर दिया जाता है। निर्णय लेने वाली समितियों और रणनीतिक पदों पर उनकी भागीदारी बेहद कम दिखाई देती है। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विशेष सत्र बुलाकर राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया था। विपक्ष पर महिलाओं के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया गया। लेकिन सवाल यह है कि यदि वास्तव में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण को लेकर गंभीर

इच्छाशक्ति होती,तो बिना किसी संवैधानिक बाध्यता के भी दल अपने स्तर पर अधिक महिलाओं को टिकट दे सकते थे। आखिर किसने रोका था कि भाजपा,कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक या अन्य दल कम से कम 33 प्रतिशत महिलाओं को उम्मीदवार बनाते? स्पष्ट है कि महिला आरक्षण का मुद्दा कई बार वास्तविक सामाजिक प्रतिबद्धता से अधिक राजनीतिक लाभ का माध्यम बन जाता है।

हालांकि यह भी स्वीकार करना होगा कि राजनीति में महिलाओं की बे ती भागीदारी लोकतंत्र को अधिक संवेदनशील और मानवीय बना सकती है। विश्व के अनेक देशों के अनुभव बताते हैं कि जहां महिलाओं की राजनीतिक उपस्थिति बढ़ी है, वहां शिक्षा, स्वास्थ्य,पोषण,जल संरक्षण,बाल सुरक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे विषयों को अधिक प्राथमिकता मिली है। भारत में पंचायत स्तर पर महिला आरक्षण के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। अनेक महिला सरपंचों और जनप्रतिनिधियों ने गांवों में शिक्षा, स्वच्छता और महिला सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे लोकतंत्र अधिक समावेशी बनता है। महिलाओं की उपस्थिति केवल संख्या का प्रश्न नहीं, बल्कि दृष्टिकोण का भी प्रश्न है। महिलाएं समाज के उन अनुभवों और समस्याओं को सामने लाती हैं,जिन्हें पुरुष प्रधान राजनीति अक्सर नजरअंदाज कर देती है। घरेलू हिंसा,मातृत्व स्वास्थ्य, कार्यस्थल सुरक्षा,बालिका शिक्षा और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को मजबूती तभी मिलती है, जब निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी हो।

लेकिन दूसरी ओर कुछ चुनौतियां भी हैं, जिनकी चर्चा आवश्यक है। कई बार राजनीतिक दल केवल औपचारिकता निभाने के लिए महिलाओं को टिकट देते हैं। ऐसे मामलों में वास्तविक सत्ता उनके परिवार के पुरुष सदस्यों के हाथ में रहती है। पंचायतों में सरपंच पति जैसी प्रवृत्तियां इसका उदाहरण हैं। राजनीति में वंशवाद और परिवारवाद के कारण भी कई योग्य महिलाएं अवसर से वंचित रह जाती हैं, जबकि राजनीतिक परिवारों से जुड़ी महिलाओं को अपेक्षाकृत आसान प्रवेश मिल जाता है। इसलिए केवल आरक्षण पर्याप्त नहीं,बल्कि राजनीतिक प्रशिक्षण,आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र नेतृत्व क्षमता का विकास भी आवश्यक है। एक अन्य चुनौती चुनावी राजनीति का बढ़ता अपराधीकरण और अत्यधिक खर्च है। भारतीय राजनीति में चुनाव लड़ना अत्यंत महंगा और संघर्षपूर्ण हो गया है। धनबल और बाहुबल की संस्कृति महिलाओं की भागीदारी को सीमित करती है। सामाजिक रूढ़ियां भी बड़ी बाधा हैं। आज भी अनेक परिवार राजनीति को महिलाओं के लिए उपयुक्त क्षेत्र नहीं मानते। देर रात की राजनीतिक गतिविधियां, सार्वजनिक आलोचना और चरित्र हनन की आशंकाएं भी महिलाओं को राजनीति से दूर करती हैं।

सवाल यह भी है कि क्या केवल आरक्षण से समस्या हल हो जाएगी? संभवतः नहीं। आरक्षण एक आवश्यक शुरुआत हो सकता है,लेकिन इसके साथ सामाजिक सोच में परिवर्तन भी जरूरी है। राजनीतिक दलों को अपने संगठनात्मक ढांचे में महिलाओं को निर्णायक भूमिका देनी होगी। उन्हें केवल चुनावी पोस्टर या प्रचार अभियान तक सीमित रखने की प्रवृत्ति बदलनी होगी। राजनीतिक प्रशिक्षण शिविर,आर्थिक सहयोग और सुरक्षित राजनीतिक वातावरण तैयार करना भी आवश्यक है। आज आवश्यकता इस बात की है कि महिला प्रतिनिधित्व को दया,उपकार या राजनीतिक मजबूरी के रूप मेंनहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकार के रूप में देखा जाए। जब तक राजनीतिक दल स्वेच्छा से महिलाओं को पर्याप्त अवसर नहीं देंगे,तब तक लोकतंत्र का संतुलन अधूरा रहेगा। यह भी सच है कि महिलाओं को भी अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग और संगठित होना होगा। राजनीतिक चेतना और नेतृत्व क्षमता के विकास के बिना केवल संवैधानिक प्रावधान अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाएंगे।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ना केवल महिलाओं का प्रश्न नहीं,बल्कि लोकतंत्र की गुणवत्ता का प्रश्न है। यदि आधी आबादी निर्णय प्रक्रिया से बाहर रहेगी,तो लोकतंत्र भी आधा-अधूरा ही रहेगा। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि महिला सशक्तीकरण केवल भाषणों और घोषणाओं से नहीं आएगा, बल्कि वास्तविक प्रतिनिधित्व और समान अवसरों से आएगा। कथनी और करनी के इस अंतर को समाप्त किए बिना महिला आरक्षण का सपना अधूरा ही रहेगा। निश्चय ही हालिया विधानसभा चुनावों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राजनीतिक दलों की महिला हितैषी राजनीति अभी भी बड़े पैमाने पर प्रतीकात्मक है। जब तक महिलाओं को टिकट वितरण,संगठनात्मक नेतृत्व और नीति निर्माण में न्यायसंगत भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक आधी दुनिया लोकतंत्र के हाशिये पर ही खड़ी दिखाई देगी।

माध्यमिक शिक्षा में बढ़ती ड्रॉपआउट दर विकसित भारत के सपनों पर संकट?

सुभाष बुड़ावन
वाला,रतलाम,मध्यप्रदेश

हाल ही में नीति आयोग की मई 2026 की रिपोर्ट 'भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली' ने देश की शिक्षा व्यवस्था की एक गंभीर तस्वीर सामने रखी है। रिपोर्ट के अनुसार माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर अभी भी सबसे अधिक है और वर्ष 2024-25 में यह राष्ट्रीय औसत 11.5 प्रतिशत रही। अर्थात आज भी हर दस में से एक छात्र दसवीं या बारहवीं तक पहुंचने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देता है। यह स्थिति केवल शिक्षा का संकट नहीं,बल्कि भारत के भविष्य,रोजगार और सामाजिक विकास से जुड़ा बड़ा खतरा है।

आज दुनिया तेजी से डिजिटल और आर्टि फिशियल इंटेलिजेंस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है ।आने वाला समय केवल उन्हीं युवाओं का होगा जो तकनीक, डिजिटल उपकरणों, कंप्यूटर,लैपटॉप,मोबाइल और एआई आधारित प्रणालियों को समझते होंगे। ऐसे में जो छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ देंगे,वे आधुनिक रोजगार की दौड़ में बहुत पीछे छूट जाएंगे। इससे सामाजिक असमानता और बेरोजगारी दोनों बढ़ सकती हैं।

रिपोर्ट में आर्थिक दबाव, कम उम्र में काम-धंधे में लग जाना, पारिवारिक जिम्मेदारियां और संस्थागत सहयोग की कमी को प्रमुख कारण बताया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक परिवार आज भी बच्चों की पढ़ाई से अधिक उनकी कमाई को प्राथमिकता देते हैं। विशेष रूप से गरीब और श्रमिक परिवारों में किशोर अवस्था आते-आते बच्चे खेत, दुकान, फैक्ट्री या दिहाड़ी मजदूरी में लग जाते हैं। लड़कियों के मामले में बाल विवाह, सुरक्षा संबंधी चिंताएं और सामाजिक रूढ़ियां भी पढ़ाई में बाधा बनती हैं।
एक अन्य महत्वपूर्ण कारण डिजिटल असमानता है। कोरोना काल के बाद शिक्षा का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन और तकनीक आधारित हो गया, लेकिन आज भी देश के लाखों छात्रों के पास स्मार्टफोन,इंटरनेट या डिजिटल संसाधनों की पर्याप्त सुविधा नहीं है। कई राज्यों में सरकारी स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर और प्रशिक्षित शिक्षक तक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। इससे छात्र पढ़ाई में रुचि खो देते हैं और धीरे-धीरे स्कूल से दूर हो जाते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि माध्यमिक शिक्षा छोड़ने वाले छात्रों का भविष्य अधिक असुरक्षित हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्टें भी संकेत देती हैं कि कम शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी और कम आय की संभावना अधिक रहती है। वहीं, एआई और ऑटोमेशन के दौर में सामान्य श्रम आधारित नौकरियां तेजी से घट सकती हैं। इसलिए माध्यमिक शिक्षा अब केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन कौशल और रोजगार सुरक्षा की आधारशिला बन चुकी है।
सरकार को इस दिशा में गंभीर और दीर्घकालिक कदम उठाने होंगे। गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति,मुफ्त डिजिटल उपकरण,इंटरनेट सुविधा और कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है। स्कूलों में करियर मार्गदर्शन, मानसिक परामर्श और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाने चाहिए। साथ ही, अभिभावकों में शिक्षा के महत्व को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाना समय की मांग है।

यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं होगा,बल्कि हर बच्चे को माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करनी होगी। क्योंकि आज का छात्र ही कल का वैज्ञानिक,इंजीनियर,शिक्षक और नीति निर्माता बनेगा। शिक्षा से दूर होता हर बच्चा वास्तव में देश के भविष्य से दूर होता भारत है।

राम के नाम से मस्तिष्क में आती है आत्मज्ञान

संजय गोस्वामी दुंदी बाजार,पटना

जब मस्तिष्क का जब दसवां भाग भी सही तरह से मनुष्य यूज नहीं कर रहा रहा।तो उसका एक मात्र कारण है आत्मज्ञान का अभाव। ध्यान की प्रगाढ़ता से मस्तिष्क तंत्र अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं। ब्रह्म तेज से मस्तिष्क की सभी तंत्रिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए ध्यान में बैठना चाहिए। ब्रह्म प्रकाश से बहुत से तंत्रिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। सारे अलग-अलग प्राणीयो के झुंड में से एक एक प्राणी को थोड़ा दुर लेजाकर छोड़ दो तो समझ लेना वो वहां ही जायेगा जहां उनकी जात के प्राणी हो, इससे सिख मिलता है कि अवश्य हमें भी अपने ही साथी जनों के साथ रहना चाहिए अन्यथा दुसरे तो घेराव बना कर तोड़-मरोड़ देंगे मीराबाई ने जो अपने गुरु से दीक्षा ली है वो श्री राम नाम की ली है संत शिरोमणि रविदास जी से ली है रविदास जी श्री रामानंद जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य हैं ! -नींद में सुधार- कुछ शोध बताते हैं कि शांत, सुकून देने वाला भगवान राम का ध्यान नींद की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है. ! रोग प्रतिरोधक क्षमता नियमित रूप से भगवान राम के ध्यान से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत हो सकती है ! संक्षेप में, भगवान राम की दया और करुणामई कार्य को ध्यान कर मस्तिष्क एक सुकून और जिस चीज में मोह का अनुभव करता है वो भगवान राम की त्याग की भावनाओं, यादों और से शारीरिक प्रतिक्रियाओं को एक साथ प्रभावित करता है, जिससे समग्र मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है ! अगर आप अपने शरीर को मज़बूत बनाना चाहते हैं, तो जिम ना जाकर पहले मस्तिष्क को गलत विचारसे मु_त हो जाएँ। अगर आप अपने दिमाग़ की कसरत करना चाहते हैं, तो राम का भजन और संगीत सुनें। बहुत कम चीजें हैं जो रामरस आपके मस्तिष्क को उत्तेजित करती हैं। अगर आप उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के दौरान अपने मस्तिष्क को सक्रिय रखना चाहते हैं, तो भगवान राम का शान्ति मन से ध्यान करें और चुप रहें उनपर छो दीजिए वो जो करेंगे ेई और नहीं कर सकता है क्योंकि सृष्टि को उसी ने रचना की है राम नाम का ध्यान करने से चिंता, रक्तचाप और दर्द कम हो सकता है, ।

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

ऑनलाइन सट्टे की लत ने ली युवा कारोबारी की जान

लाखों के कर्ज और मानसिक दबाव से टूटा व्यवसायी,सुसाइड नोट में छलकाया दर्द

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 मई 2026
(घटती-घटना)।

ऑनलाइन सट्टे की बढ़ती लत अब लोगों की जिंदगी पर भारी पडने लगी है। शहर के मायापुर निवासी एक युवा व्यवसायी ने लाखों रुपए के कर्ज और मानसिक तनाव से परेशान होकर जहर सेवन कर आत्मघाती कदम उठा लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। मृतक ने मरने से पहले पत्नी और पिता के नाम सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने अपने हालात, कर्ज और सट्टे की बुरी आदत का जिक्र करते हुए माफी मांगी है। जानकारी के अनुसार मायापुर निवासी संदीप अग्रवाल (40) पुराना बस स्टैंड स्थित दुर्गा बाड़ी के सामने ड्राइफ्रूट्स की दुकान संचालित करता था। शुक्रवार दोपहर करीब 12.30 बजे वह दुकान से घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने अपने पिता से कहा कि अब वह परिवार को परेशान नहीं करेगा। उसने बताया कि दुकान में कीटनाशक का सेवन कर लिया है। यह सुनते ही परिजनों के पैरों तले

जमीन खिसक गई। घर में अफरा-तफरी मच गई और तत्काल उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन उसे मिशन अस्पताल लेकर पहुंचे,जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जांच शुरू की।

क्रिकेट सट्टे में हार चुका था लाखों रुपए

परिजनों ने बताया कि संदीप पिछले कुछ समय से ऑनलाइन सट्टे की गिरफ्त में था। वह क्रिकेट मैचों में ऑनलाइन पैसा लगाता था। शुरुआत में छोटे दांव लगाने वाला संदीप धीरे-धीरे बड़े अमाउंट तक पहुंच गया। लगातार हार के कारण उस पर लाखों रुपए का कर्ज हो गया था। बताया जा रहा है कि कर्ज चुकाने के लिए वह कई लोगों से रुपए उधार ले चुका था। कारोबार में भी नुकसान हो रहा था। ऐसे में आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता गया। परिजन कई बार उसे समझाते रहे, लेकिन वह इस लत से बाहर नहीं निकल सका।

सुसाइड नोट में छलका दर्द

मृतक ने पत्नी और पिता के नाम अलग-अलग सुसाइड नोट छोड़ा है। नोट में उसने अपने किए पर पछतावा जताते हुए परिवार से माफी मांगी है। उसने लिखा कि उसके ऊपर काफी कर्ज हो चुका है और अब वह उसे चुका पाने की स्थिति में नहीं है। सुसाइड नोट में उसने यह भी लिखा कि कई लोगों ने ऊंचे ब्याज पर उसे पैसे दिए और लंबे समय तक ब्याज लेते रहे। कुछ लोग उसे सट्टा खिलाते थे और हारने के बाद पैसों के लिए दबाव बनाते थे। हालांकि उसने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिखा है। पुलिस के अनुसार सुसाइड नोट में किसी को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। फिलहाल नोट को जब्त कर जांच में शामिल किया गया है।

परिवार की जिम्मेदारी भी थी कंधों पर

संदीप अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी। घर में पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं। पिता की तबीयत भी अक्सर खराब रहती है। ऐसे में परिवार पूरी तरह संदीप पर निर्भर था। घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। मोहल्ले के लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि संदीप मिलनसार स्वभाव का था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह काफी तनाव में रहने लगा था।

तेजी से बढ़ रहा ऑनलाइन सट्टे का जाल : शहर में ऑनलाइन सट्टे और गेमिंग एप्स का जाल तेजी से फैल रहा है। मोबाइल फोन के जरिए युवा आसानी से सट्टेबाजी की दुनिया में पहुंच रहे हैं। शुरुआत में कम रकम जीतने के लालच में लोग इसमें शामिल होते हैं, लेकिन बाद में भारी नुकसान और कर्ज के कारण मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऑनलाइन सट्टा आर्थिक ही नहीं,मानसिक और सामाजिक रूप से भी लोगों को बर्बाद कर रहा है। कई मामलों में लोग कर्ज, दबाव और बदनामी के डर से गलत कदम उठा लेते हैं।

पुलिस कर रही मामले की जांच

कोतवाली थाना प्रभारी शशिकांत सिन्हा ने बताया कि मृतक ने पत्नी और पिता के नाम से दो सुसाइड नोट छोड़े हैं। नोट में कर्ज, व्यापार में नुकसान और सट्टे का जिक्रहै। किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिखा गया है। मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि मृतक किन लोगों के संपर्क में था और उस पर किस प्रकार का आर्थिक दबाव था। वहीं घटना के बाद शहर में ऑनलाइन सट्टे के बढ़ते दुष्प्रभाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

अवैध रूप से बीयर ले जा रहे दो आरोपी गिरफ्तार,24 केन बीयर और बाइक जब्त

वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर भागने लगे आरोपी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 मई 2026 (घटती-घटना)।

रघुनाथनगर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान अवैध रूप से बीयर परिवहन कर रहे दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 24 नग केन बीयर एवं एक मोटरसाइकिल जब्त कर दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर 8 मई 2026 को थाना रघुनाथनगर क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान शाम करीब 5 बजे ग्राम केसारी की ओर से आ रही एक होंडा एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल में सवार दो युवक पुलिस चेकिंग देखकर घबरा गए और भागने का प्रयास करने लगे। संदेह होने पर पुलिस टीम ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में बाइक चालक ने अपना नाम श्याम कार्तिक कुशवाहा पिता गोरेलाल कुशवाहा उम्र 25 वर्ष तथा पीछे बैठे युवक ने अपना नाम मनीष साहू पिता राम लल्लू साहू उम्र 22 वर्ष बताया। तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल में रखी सफेद रंग की बोरी से 24 नग किंगफिशर केन बीयर बरामद हुई, जिसकी

कीमत करीब 3 हजार 360 रुपए बताई गई है। बीयर के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर पुलिस ने मौके पर ही बीयर एवं मोटरसाइकिल जब्त कर ली। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना रघुनाथनगर में अपराध क्रमांक 48/26 के तहत धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

आंधी-बारिश से बदला मौसम...गर्मी से राहत लेकिन नुकसान भी

50 किमी की रफ्तार से चली हवा, कई जगह पेड़ गिरे और उड़े मकानों के शेड

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 मई 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा संभाग में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच शुक्रवार शाम मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज आंधी और हल्की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी, लेकिन कई इलाकों में नुकसान भी पहुंचाया। तेज हवा के कारण शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ गिर गए, जबकि कई मकानों के टीन शेड उड़ गए। शुक्रवार शाम अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। कुछ देर बाद हल्की बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग के अनुसार आंधी की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही। तेज हवा के कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। शहर के बनारस मार्ग स्थित डाइट कॉलेज के पास एक बड़ा पेड़ सड़क किनारे खड़ी दो स्कूटी पर गिर गया। हादसे में स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि घटना के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा

टल गया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेड़ गिरने और घरों के शेड उडने की सूचना मिली है।

तीन-चार दिनों से बदल रहा मौसम : अंबिकापुर सहित सरगुजा संभाग में पिछले तीन से चार दिनों से दोपहर बाद मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। कभी बादल छा रहे हैं तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। मौसम में इस बदलाव से दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कुछ दिन पहले तक अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा था,लेकिन अब बारिश और बादलों की सक्रियता से मौसम सुहाना हो गया है। अधिकतम तापमान गिरकर 34 से 35 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 20.9 डिग्री दर्ज किया गया।

पश्चिमी विक्षोभ का असर

मौसम वैज्ञानिक एएम भट्ट ने बताया कि मन्नार की खाड़ी और उससे लगे श्रीलंकाई क्षेत्र के ऊपर 5.8 किलोमीटर ऊंचाई पर चक्रवाती वायु परिसंचरण बना हुआ है। इसके प्रभाव से आगामी 11 मई के आसपास दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में निम्न वायुदाब क्षेत्र बनने की संभावना है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव हो रहा है। आने वाले कुछ दिनों तक अंबिकापुर सहित सरगुजा संभाग में तेज आंधी और बारिश की स्थिति बनी रह सकती है।

गर्मी से मिली राहत

तेज गर्मी और उमस से परेशान लोगों को मौसम बदलने से राहत मिली है। शाम होते ही ठंडी हवा चलने लगी, जिससे लोगों ने राहत महसूस की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह बने रहने की संभावना जताई है।

सुशासन तिहार में उमड़ा जनसैलाब...गांव-गांव पहुंचा प्रशासन

घोघरा और झेराडीह शिविर में सैकड़ों आवेदनों का निराकरण,सांसद-विधायकों ने अधिकारियों को दिए निर्देश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 मई 2026
(घटती-घटना)।

जिले में चल रहे 'सुशासन तिहार-2026' के तहत शनिवार को बतौली विकासखंड के घोघरा और लुण्ड्रा विकासखंड के झेराडीह में जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और अपनी समस्याओं व मांगों से जुड़े आवेदन प्रशासन को सौंपे। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर कई समस्याओं का निराकरण किया, वहीं शेष आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजा गया। शिविरों में सांसद चिंतामणि महाराज,सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो,लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज, संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा और कलेक्टर अजीत वसंत सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को समयसीमा में समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए।

घोघरा शिविर में पहुंचे 14 पंचायतों के ग्रामीण : बतौली विकासखंड के घोघरा स्थित माध्यमिक शाला परिसर में आयोजित शिविर में 14 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण शामिल हुए। घोघरा, मानपुर, शिवपुर,टेड़गा,सल्याडीह, बांसाझाल, टीरंग, बोदा, बिलासपुर, घुटरापारा, तरागी, ललाती, पोपरेंगा और सिलमा पंचायतों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। शिविर में विभिन्न विभागों ने योजनाओं की जानकारी दी और पात्र हितग्राहियों को लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। यहां कुल 738 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 730 मांग और 8 शिकायत संबंधी थे। प्रशासन ने मौके पर 115 आवेदनों का निराकरण किया, जबकि शेष मामलों को संबंधित विभागों को भेजा गया।

झेराडीह में भी लगा समाधान शिविर : लुण्ड्रा विकासखंड के झेराडीह स्थित प्राथमिक शाला और पंचायत भवन परिसर में भी जनसमस्या निवारण शिविर लगाया गया। शिविर में झेराडीह, बरगीडीह, गढ़बीरा, सिलसिला, लमगांव, असकला, कोट, गंगापुर, गेरसा, जरहाडीह, महोरा और ससौली सहित 20 पंचायतों के ग्रामीण शामिल हुए। ग्रामीणों ने राजस्व,पेयजल, बिजली, पेंशन, राशन कार्ड और अन्य समस्याओं से जुड़े आवेदन दिए। अधिकारियों ने गंभीरता से सुनवाई कर कई मामलों का तत्काल समाधान किया।

बिजली बिल और पेयजल समस्या पर सांसद सख्त

सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से प्रशासन खुद गांवों तक पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहा है। उन्होंने अधिकारियों को नामांकन, सीमांकन और बंटवारे जैसे अविवादित राजस्व प्रकरणों का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। सांसद ने ग्रामीणों की बिजली बिल संबंधी शिकायतों पर जांच कर समाधान करने और पात्र हितग्राहियों को मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना का लाभ दिलाने को कहा। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को खराब बोरिंग और बोरवेल की मरम्मत कर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। श्रम विभाग को श्रमिक पंजीयन बढ़ाने और किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।

10 जून तक चलेगा अभियान

सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने ग्रामीणों से शिविरों का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की। वहीं लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर सुशासन तिहार आम जनता की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बन रहा है। संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा ने कहा कि शिविरों का उद्देश्य लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए कार्यालयों के चक्कर से बचाना है। उन्होंने अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों के निराकरण की सूचना संबंधित आवेदकों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रशासन गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है। यह अभियान 10 जून तक लगातार जारी रहेगा और सभी आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

29 विभागों के स्टॉल बने आकर्षण का केंद्र : शिविरों में कृषि, उद्यानिकी, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, पंचायत, राजस्व और ग्रामीण विकास सहित 29 से अधिक विभागों के स्टॉल लगाए गए। अधिकारियों ने ग्रामीणों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कई पात्र हितग्राहियों से आवेदन भी भरवाए गए। राशन कार्ड, पेंशन और राजस्व अभिलेखों से जुड़े कई मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया।

नेत्रदान व अंगदान जागरूकता के लिए सरगुजा की आकांक्षा श्रीवास्तव सम्मानित

विश्व रेड क्रॉस दिवस पर रायपुर में मिला राज्य स्तरीय विशेष सम्मान

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 मई 2026
(घटती-घटना)।

विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी,जिला शाखा सरगुजा की आजीवन सदस्य आकांक्षा श्रीवास्तव को नेत्रदान,अंगदान एवं देहदान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, छत्तीसगढ़ राज्य शाखा द्वारा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी सभाकक्ष, मेकाहारा हॉस्पिटल परिसर रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया। कार्यक्रम राज्यपाल एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ राज्य शाखा के अध्यक्ष रमेन डेका के संरक्षण में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री गजेंद्र यादव सहित अन्य मौजूद रहे। राज्य शाखा के चेयरमैन तोमन साहू, वाइस चेयरमैन रुपेश कुमार पाणिग्राही एवं कोषाध्यक्ष संजय पटेल के नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ। रेड क्रॉस सोसायटी के अनुसार नेत्रदान, अंगदान और देहदान के क्षेत्र में जनजागरूकता एवं मानव सेवा के लिए पूरे छत्तीसगढ़ से केवल सरगुजा जिला शाखा की सदस्य आकांक्षा श्रीवास्तव को यह विशेष सम्मान दिया गया। इसे सरगुजा जिले और रेड क्रॉस परिवार के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से आए करीब 2800 प्रतिभागियों,स्वयंसेवकों,छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान रक्तदान,अंगदान,मानव सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़े कई जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य स्तरीय आयोजन में भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी जिला शाखा सरगुजा की ओर से छात्राओं की टीम ने भी हिस्सा लिया। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर की 21 छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम,क्षेत्रीय गीत आधारित समूह नृत्य, अंगदान विषय पर नाटक और चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेकर जिले का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी जिला शाखा सरगुजा के चेयरमैन आदित्येश्वर शरण सिंह देव ने आकांक्षा श्रीवास्तव को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान पूरे सरगुजा जिले के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस सोसायटी हमेशा मानव सेवा, सामाजिक जागरूकता और जनकल्याण के कार्यों के लिए प्रतिबद्ध रही है। जिला शाखा के पदाधिकारियों, स्वयंसेवकों और सदस्यों ने भी आकांक्षा श्रीवास्तव एवं कार्यक्रम में शामिल छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं दीं।

कमीशन के लालच में युवाओं ने दिए बैंक खाते,साइबर फ्रॉड गिरोह से जुड़े 10 आरोपी गिरफ्तार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 मई 2026
(घटती-घटना)।

आसान कमाई और कमीशन के लालच में अपने बैंक खाते साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराना शहर के 10 युवकों को भारी पड़ गया। गांधीनगर पुलिस ने साइबर ठगी से जुड़े मामले में कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ऑनलाइन फ्रॉड की रकम अपने खातों में लेकर एटीएम और सीडीएम मशीन के जरिए दूसरे खातों में ट्रांसफर करते थे। गांधीनगर थाना में ग्राम पंचायत सकालो चाना निवासी सुजीत मंडल की शिकायत पर अपराध क्रमांक 649/2025 धारा 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच के दौरान पहले अनीश गिरी, सद्दाम आलम और वर्षा सिंह पोर्ते को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में कई अन्य युवकों के नाम सामने आए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज की। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी कुछ पैसों और कमीशन के बदले अपने बैंक खाते साइबर अपराधियों को उपयोग करने देते थे। खातों में ऑनलाइन ठगी और गेमिंग से जुड़ी रकम जमा होती थी, जिसे आरोपी एटीएम से निकालकर या सीडीएम मशीन के जरिए अन्य खातों में जमा करते थे। पुलिस ने 10 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की,जहां सभी ने अपराध में शामिल होने की बात स्वीकार की। आरोपियों के कब्जे से 10 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। बैंक खातों की जांच में यह भी पता चला कि अन्य राज्यों में भी इन खातों के खिलाफ शिकायतें और अपराध दर्ज हैं। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

साइबर अपराधियों के 'म्यूल अकाउंट' बने युवक : पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी अपने बैंक खातों को 'म्यूल अकाउंट' की तरह इस्तेमाल करने दे रहे थे। साइबर अपराधी ऐसे खातों का उपयोग ठगी की रकम छिपाने और एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करने के लिए करते हैं।

पुलिस की अपील : लालच से बचें, खाते और सिम किसी को न दें : सरगुजा पुलिस ने आम नागरिकों, खासकर युवाओं और अभिभावकों से अपील की है कि वे किसी भी लालच या फर्जी ऑफर के झांसे में न आएं। अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, ओटीपी, यूपीआई पिन और पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें। पुलिस ने कहा कि 'घर बैठे कमाई ', 'कम समय में ज्यादा मुनाफा' और 'आसान ऑनलाइन इनकम' जैसे ऑफर साइबर ठगी का हिस्सा हो सकते हैं।

थोड़े से लालच में आकर किया गया काम बड़ी कानूनी परेशानी और सजा का कारण बन सकता है। प्रकरण की कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण द्विवेदी,प्रधान आरक्षक सुधीर सिंह,आरक्षक अमृत सिंह, अरविंद उपाध्याय,ऋषभ सिंह तथा साइबर थाना के प्रवीण प्रताप सिंह और विकास तिर्की की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

जन्मदिन या पोस्टिंग दरबार? विधायक के मंच पर अफसरों की भीड़ से उठे सवाल

क्या विधायक की 'छत्रछाया' में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अधिकारी?

- विधायक के जन्मदिन में अफसरों का जमावड़ा, प्रशासनिक मर्यादा पर बहस तेज
- गाना,आशीर्वाद और मंचीय मौजूदगी – प्रेमनगर में अफसरों की 'राजनीतिक एक्टिविटी' चर्चा में
- क्या अब पोस्टिंग का रास्ता जन्मदिन मंच से होकर गुजरता है?
- विधायक के जन्मदिन में पहुंचे अधिकारी,सोशल मीडिया में वायरल हुई प्रशासनिक नजदीकी
- सरकारी अफसर या राजनीतिक समर्थक? प्रेमनगर कार्यक्रम ने खड़े किए बड़े सवाल
- मंच पर अफसर, हाथ में माइक और सामने विधायक – सूरजपुर में चर्चा गर्म
- जन्मदिन समारोह में प्रशासनिक 'हाजिरी', जिले में उठे निष्पक्षता पर सवाल
- केक कटिंग से ज्यादा चर्चा अफसरों की मौजूदगी की, प्रेमनगर कार्यक्रम बना मुद्दा
- पैर छूने से गाना गाने तक – विधायक के जन्मदिन में अफसरों की भूमिका चर्चा में
- लाइन से मंच तकः थाना चाहने वाले पुलिसकर्मियों की मौजूदगी ने बढ़ाई चर्चा

क्या पोस्टिंग का रास्ता जन्मदिन मंच से होकर गुजरता है?

जिले में यह चर्चा भी खूब हो रही है कि कार्यक्रम में कुछ ऐसे पुलिसकर्मी भी मौजूद थे जो वर्तमान में लाइन में हैं और थाना प्रभार की उम्मीद लगाए बैठे हैं, इसी को लेकर लोग व्यंग्य कर रहे हैं अब थाना पाने के लिए आवेदन एसपी ऑफिस में नहीं, जन्मदिन मंच पर देना पड़ेगा क्या? हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जिस तरह कार्यक्रम में कुछ अधिकारियों की सक्रियता दिखाई दी, उसने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है,स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि अधिकारी सार्वजनिक रूप से राजनीतिक संरक्षण की तरफ झुकते दिखाई देंगे,तो इससे पूरी प्रशासनिक निष्पक्षता पर असर पड़ेगा।

-शमरोज खान-

सूरजपुर 09 मई 2026 (घटती-घटना)।

प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी का जन्मदिन समारोह अब केवल एक राजनीतिक आयोजन नहीं रह गया है,बल्कि जिले में प्रशासनिक लोकाचार,सरकारी मर्यादा और राजनीतिक संरक्षण संस्कृति को लेकर बड़ी बहस का विषय बन चुका है, कार्यक्रम में जिस तरह प्रशासनिक अधिकारियों,पुलिस कर्मचारियों और विभागीय अफसरों का जमावड़ा दिखाई दिया, उसने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर यह जन्मदिन समारोह था या फिर 'सुरक्षित भविष्य' की सामूहिक हाजिरी, जिले में चर्चा इस बात की सबसे ज्यादा है कि कार्यक्रम में पहुंचे कई अधिकारी ऐसे दिखाई दिए मानो वे केवल शुभकामना देने नहीं,बल्कि अपनी प्रशासनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पहुंचे हों। मंचीय सक्रियता, विधायक के लिए गीत गाना,पैर छूकर आशीर्वाद लेना और महंगे उपहारों के साथ मौजूदगी ने पूरे आयोजन को राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से संवेदनशील बना दिया है।

विधायक की 'छत्रछाया' में सुरक्षित महसूस कर रहे अफसर?

कार्यक्रम के बाद जिले में सबसे ज्यादा यही चर्चा चल रही है कि क्या अब अधिकारियों को अपने विभागीय काम और कार्यप्रणाली से ज्यादा राजनीतिक समीकरणों पर भरोसा होने लगा है, लोगों का कहना है कि जिस प्रकार विभिन्न विभागों के अधिकारी और पुलिस कर्मचारी कार्यक्रम में सक्रिय दिखाई दिए, उससे यह संदेश गया कि कई अधिकारी विधायक की नजदीकी को अपने लिए सुरक्षा कवच मान रहे हैं, स्थानीय लोगों के बीच यह भी चर्चा है कि प्रशासनिक व्यवस्था में अब 'काम' से ज्यादा 'संबंध' महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, यही कारण है कि जन्मदिन समारोह में मौजूदगी केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह सार्वजनिक निष्ठा प्रदर्शन जैसी दिखाई दी।

मंच पर गाना और 'राजनीतिक सुर

कार्यक्रम में कुछ अधिकारियों द्वारा विधायक के लिए गीत गाना अब पूरे जिले में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है, सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकारी अधिकारी अब प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ राजनीतिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देंगे? व्यंग्य में लोग कह रहे हैं अब शायद अच्छी पोस्टिंग के लिए फाइल से ज्यादा सुर और ताल जरूरी हो गए हैं, सरकारी बैठकों में जहां आम जनता को अधिकारी मुश्किल से समय दे पाते हैं, वहीं मंच पर उनकी सक्रियता ने लोगों को चौंका दिया।

पैर छूकर आशीर्वाद और प्रशासनिक मर्यादा

कार्यक्रम का सबसे संवेदनशील पहलू वह वीडियो माना जा रहा है जिसमें एक अधिकारी विधायक का पैर छूकर आशीर्वाद लेते दिखाई दिए, इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई, लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक प्रशासनिक अधिकारी को सार्वजनिक मंच पर इस तरह राजनीतिक रूप से झुकाव दिखाना चाहिए? क्या इससे प्रशासनिक निष्पक्षता प्रभावित नहीं होती? कई लोगों का कहना है कि सम्मान देना भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन जब वही सम्मान सार्वजनिक मंच पर 'राजनीतिक निकटता' का प्रतीक बन जाए, तब सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है।

महंगे तोहफे और 'निष्ठा प्रदर्शन' की चर्चा

कार्यक्रम के बाद यह चर्चा भी तेज है कि कुछ अधिकारी महंगे उपहार लेकर पहुंचे थे,हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है,लेकिन जिले में यह बात लगातार चर्चा का हिस्सा बनी हुई है, लोग सवाल उठा रहे हैं कि यदि कोई अधिकारी किसी जनप्रतिनिधि के इतने करीब सार्वजनिक रूप से दिखाई देता है,तो क्या भविष्य में वह उसी जनप्रतिनिधि से जुड़े मामलों में निष्पक्ष निर्णय ले पाएगा?

जनता पूछ रही...फिर फटकार कौन लगाएगा?

सबसे बड़ा सवाल अब यही बन चुका है कि जो अधिकारी सार्वजनिक मंच पर विधायक के लिए गीत गाते दिखाई दें,आशीर्वाद लेते दिखाई दें और राजनीतिक निकटता प्रदर्शित करें, क्या वे भविष्य में नियमों के उल्लंघन पर उसी जनप्रतिनिधि को फटकार लगा पाएंगे? क्या वे अवैध कामों पर कार्रवाई कर पाएंगे? क्या वे जनता की शिकायतों पर निष्पक्ष निर्णय ले पाएंगे? क्या वे राजनीतिक दबाव से मुक्त रह पाएंगे? यही वे सवाल हैं जो इस पूरे कार्यक्रम को सामान्य जन्मदिन समारोह से बड़ा प्रशासनिक मुद्दा बना रहे हैं।

प्रशासनिक लोकाचार पर बड़ा प्रश्न

प्रशासनिक सेवा में कार्यरत अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहें और जनता के प्रति जवाबदेह दिखाई दें, लेकिन इस पूरे आयोजन ने प्रशासनिक लोकाचार को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है, विशेषज्ञों का मानना है कि अधिकारी किसी जनप्रतिनिधि के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन मंचीय सक्रियता, सार्वजनिक निष्ठा प्रदर्शन और अत्यधिक राजनीतिक निकटता प्रशासनिक गरिमा को प्रभावित कर सकती है।

सोशल मीडिया बना जनता की अदालत

इस पूरे मामले में सोशल मीडिया ने बड़ी भूमिका निभाई। वायरल वीडियो और तस्वीरों के बाद लोगों ने खुलकर प्रतिक्रिया दी, कुछ लोगों ने इसे 'सम्मान' कहा, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इसे प्रशासनिक निष्पक्षता के खिलाफ बता रहे हैं, एक यूजर ने लिखा– 'जनता महीनों दफ्तरों के चक्कर लगाती है,लेकिन अधिकारी मंच पर गीत प्रस्तुत करने में व्यस्त हैं।' दूसरे ने लिखा– 'अब शायद सीआर नहीं, केक कटिंग उपस्थिति ज्यादा जरूरी हो गई है।'

राजनीति और प्रशासन की बढ़ती नजदीकी

भारतीय लोकतंत्र में राजनीति और प्रशासन का समन्वय आवश्यक माना जाता है, लेकिन जब यह समन्वय सार्वजनिक मंचों पर 'निकटता प्रदर्शन' में बदलता दिखाई दे, तब सवाल उठना स्वाभाविक है,विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशासनिक अधिकारी केवल निष्पक्ष हों इतना काफी नहीं, बल्कि जनता को निष्पक्ष दिखाई भी देने चाहिए,यही कारण है कि प्रेमनगर विधायक के जन्मदिन समारोह ने पूरे जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर नई बहस खड़ी कर दी है।

अब सवालों के घेरे में पूरा सिस्टम

जन्मदिन समारोह खत्म हो चुका है,लेकिन उससे उठे सवाल अभी बाकी हैं, क्या सरकारी अधिकारियों की इस तरह की सार्वजनिक राजनीतिक मौजूदगी उचित है? क्या सेवा नियमों में इसकी अनुमति है? क्या भविष्य में ऐसे मामलों पर कोई दिशा-निर्देश जारी होंगे? क्या प्रशासनिक निष्पक्षता केवल फाइलों तक सीमित रह गई है? इन सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं, लेकिन इतना तय है कि सूरजपुर जिले में यह जन्मदिन समारोह अब केवल केक काटने का कार्यक्रम नहीं रहा – यह प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक प्रभाव के रिश्ते का सार्वजनिक प्रदर्शन बन चुका है।

इन अधिकारियों की मंचीय मौजूदगी और तस्वीरें अब राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन चुकी हैं,जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें...

- विराट वीसी – थाना प्रभारी प्रेमनगर
- राजेंद्र साहू – पुलिस विभाग
- मानहरण राठिया – तहसीलदार
- सुरेश मिश्रा – एसडीओ पीडब्ल्यूडी
- सूर्यकांत साय – तहसीलदार सूरजपुर
- संजय राय – सीईओ जनपद
- बी.एस.टेकाम – विपणन अधिकारी
- डी. एस. लकड़ा – ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- अजय मिश्रा – जिला शिक्षा अधिकारी
- दीपक यादव – पुलिस विभाग
- मनोज जायसवाल –बीआरसी

भाजपा सरगुजा में नई जिम्मेदारियों का ऐलान,कार्यकर्ताओं में उत्साह

जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने नव नियुक्त पदाधिकारियों को दी बधाई,संगठन विस्तार और जनसंपर्क को बताया प्राथमिकता...

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,09 मई 2026 (घटती-घटना)।

अंबिकापुर स्थित संकल्प भवन भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भारत सिंह सिसोदिया ने भाजपा सरगुजा जिला कार्यसमिति सदस्यों, विशेष आमंत्रित सदस्यों, स्थायी आमंत्रित सदस्यों तथा मंडल प्रभारी एवं सह-प्रभारियों की घोषणा की। नई जिम्मेदारियों के ऐलान के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में जिला महामंत्री विनोद हर्ष एवं अरुणा सिंह, उपाध्यक्ष मधुसूदन शुक्ला, वरिष्ठ भाजपा नेता निलेश सिंह तथा जिला संवाद प्रमुख रूपेश दुबे की उपस्थिति में नव नियुक्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है,जहां प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि संगठन ने जिन पदाधिकारियों एवं कार्यसमिति सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी है, वे पूरी निष्ठा, समर्पण और टीम भावना के साथ कार्य करते हुए संगठन को और अधिक मजबूत बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एवं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की मंशा के अनुरूप अंतिम व्यक्ति तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना तथा संगठन की विचारधारा को जन-जन तक ले जाना सभी कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों एवं जनसंपर्क अभियानों में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान भी किया। जिला संवाद प्रमुख रूपेश दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला कार्यसमिति, विशेष आमंत्रित एवं स्थायी आमंत्रित सदस्यों की सूची में संगठन के वरिष्ठ एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं को स्थान दिया गया है।

जंगल में मिले युवक-युवती के कंकाल छह साल पहले लापता प्रेमी जोड़े होने की आशंका

कपड़ों के आधार पर परिजनों ने की पहचान,डीएनए जांच से होगी पुष्टि

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,09 मई 2026 (घटती-घटना)।

धौरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जमोनी और बिलमा के बीच जंगल में युवक और किशोरी का कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि यह कंकाल करीब छह साल पहले लापता हुए प्रेमी जोड़े के हो सकते हैं। सूचना मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार धौरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जमोनी निवासी एक युवक और किशोरी फरवरी 2020 से अचानक लापता हो गए थे। दोनों के गायब होने के बाद परिजनों ने काफी तलाश की,लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका। बताया जा रहा है कि दोनों पहले भी घर से भाग चुके थे, तब पुलिस ने उन्हें खोजकर परिजनों को सौंप दिया था। परिजनों ने करीब दो वर्षों तक अपने स्तर पर खोजबीन की। बाद में युवक के पिता ने 13 मई 2023 को धौरपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। तब से पुलिस भी मामले की जांच कर रही थी।

चूहा पकडने के दौरान बाहर निकला कंकाल : शुक्रवार को ग्राम जमोनी और बिलमा के बीच जंगल में कुछ ग्रामीण बिल खोदकर चूहा पकड़ रहे थे। इसी दौरान जमीन के अंदर से मानव कंकाल का हिस्सा बाहर निकल आया। यह देख ग्रामीण घबरा गए और तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही धौरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में फोरेंसिक विशेषज्ञों को भी बुलाया गया। जांच के दौरान वहां से युवक और किशोरी के कंकाल के अवशेष मिले।

कपड़ों से की पहचान : पुलिस ने प्रथम दृष्टया आशंका के आधार पर लापता युवक और किशोरी के परिजनों को मौके पर बुलाया। कंकाल के पास मिले कपड़ों और अन्य सामान को देखकर परिजनों ने उनकी पहचान बिनोद कोरवा और ज्योति के रूप में की। हालांकि पुलिस का कहना है कि फिलहाल यह केवल प्रारंभिक पहचान है। डीएनए जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट रूप से पुष्टि हो सकेगी कि कंकाल किसके हैं।

आज कराया जाएगा पोस्टमार्टम : धौरपुर थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों कंकालों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। प्रारंभिक जांच में हड्डियों पर किसी प्रकार के चोट के स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है।

निःशुल्क विधिक सहायता शिविर का शुभारंभ

जरूरतमंदों को प्रत्येक माह मिलेगा निःशुल्क कानूनी परामर्श : सिसोदिया

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,09 मई 2026 (घटती-घटना)।

भारत सिंह सिसोदिया की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ सरगुजा द्वारा भाजपा कार्यालय संकल्प भवन में निःशुल्क विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ भाजपा नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विद्यानंद मिश्रा ने फीता काटकर किया। अंबिकापुर में आयोजित इस शिविर को संबोधित करते हुए भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और कानूनी जानकारी पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधि प्रकोष्ठ का यह प्रयास जनसेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि जरूरतमंद लोगों को प्रत्येक माह निःशुल्क कानूनी परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। भाजपा विधि प्रकोष्ठ सरगुजा के जिला संयोजक जन्मेजय पाण्डेय ने बताया कि आमजन,गरीब,असहाय एवं जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह के दूसरे एवं तीसरे शनिवार को निःशुल्क कानूनी सहायता एवं विधिक परामर्श शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में विभिन्न सामाजिक एवं विधिक विषयों से संबंधित समस्याओं पर लोगों को मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जिले में 65 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे

सामूहिक विवाह समारोह में एक दिव्यांग (मूकबधिर) जोड़े सहित हिन्दू एवं ईसाई जोड़ों का विवाह संपन्न

-संवाददाता-

जशपुरनगर,09 मई 2026 (घटती-घटना)।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत शुक्रवार को जिले के विभिन्न परियोजना क्षेत्रों में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया,जिसमें कुल 65 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। कार्यक्रम में हिन्दू एवं ईसाई दोनों समुदायों के जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। विशेष बात यह रही कि परियोजना बगीचा में एक दिव्यांग (मूकबधिर) जोड़ा भी विवाह समारोह में शामिल हुआ, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। परियोजना बगीचा में 13 हिन्दू एवं 07 ईसाई सहित कुल 20 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। नवदंपत्तियों को आशीर्वाद देने जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मोनिका टोप्पो,सुश्री आशिका कुजूर,जनपद अध्यक्ष श्रीमती गायत्री नागेश, जनपद उपाध्यक्ष श्री अरविन्द गुप्ता,नगर पंचायत अध्यक्ष श्री प्रभात सिदाम,श्री मुकेश शर्मा,सैनिक बोर्ड अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र गुप्ता,जनपद सदस्य सविता नागेश, सीईओ जनपद पंचायत बगीचा, बीईओ बगीचा एवं बीआरसीसी संयोजक बगीचा उपस्थित रहे। परियोजना कांसाबेल में 09 हिन्दू एवं 03 ईसाई कुल 12 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष श्रीमती सरिता भगत,जनपद उपाध्यक्ष श्री प्रमोद गुप्ता,श्री सुनील गुप्ता, पूर्व जनपद अध्यक्ष श्री मोतीलाल भगत,जनपद सदस्य श्रीमती शिप्रा दास, सरपंच कांसाबेल श्री अनिल खलखो, उपसरपंच श्री अमित अग्रवाल, पूर्व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष श्री सुभाष गुप्ता, वरिष्ठ सदस्य श्री अनूप कश्यप एवं श्री संजय सिंह उपस्थित रहे। इसी प्रकार परियोजना बागबहार में 06 हिन्दू एवं 26 ईसाई कुल 32 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में श्री आनंद शर्मा, श्री मनी मुन्नी अग्रवाल, श्रीमती मीना चौहान, श्री चन्द्रचूर्ण बंजारा, जनपद सदस्य एवं बाल विकास समिति सदस्य श्री कलम विश्वकर्मा, श्री प्रितम शर्मा, श्रीमती पदमनी परहा, श्रीमती सुमित्रा पैंकरा एवं जनपद सदस्य सुश्री कुमारी नाग उपस्थित रहीं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े के लिए 50 हजार रुपये की सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें 8 हजार रुपये आयोजन व्यय,7 हजार रुपये की उपहार सामग्री तथा वधु को 35 हजार रुपये का चेक एवं वैवाहिक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान नवदंपत्तियों को सुखमय वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी गईं तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।

न्यायालय नायब तहसीलदार सूरजपुर-01,जिला-सूरजपुर,छ0ग0

ईश्तहार

रा0प्र0क्र0 /अ-6-अ/2025-26

ग्राम - देवीपुर

एतद् द्वारा सर्व साधारण ग्राम देवीपुर को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुनील सिंह उर्फ देवेन्द्र प्रताप आ0 रेवती रमण अन्य-01 जाति गोंड़ निवासी ग्राम श्यामपुर तहसील प्रेमनगर जिला सूरजपुर (छ0ग0) के द्वारा ग्राम देवीपुर पहन0 13 स्थित भूमि कुल खसरा न0 08 योग रकबा 2.4240 हे0 भूमि के राजस्व अभिलेखों आवेदकगण का नाम त्रुटिवश देवेन्द्र प्रताप एवं अर्जुन सिंह अंकित हो गया है। जो घरेलु एवं पुकारू नाम है। जिसे विलोपित कराकर आवेदकगण अपना नाम सुनिल सिंह एवं अमित कुमार सिंह कराने हेतु शपथ पत्र, आधार कार्ड, अंक सूची एवं खसरा बी-1 की छाया प्रति सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर नाम सुधार की कवाही प्रारम्भ कर दी गई है। इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति या कोई संस्था को आपत्ति हो तो दिनांक 14/05/2026 को समय 11.00 बजे इस न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा ।

आज दिनांक 29/04/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी ।

सील — नायब तहसीलदार सूरजपुर-01

न्यायालय नायब तहसीलदार पटना-जिला कोरिया ,छ0ग0

रा0प्र0क्र0 .....

ईश्तहार

एतद् द्वारा समस्त ग्रामीण जनता ग्राम रनई को सूचित किया जाता है कि आवेदक आशीष कुमार आ0 राजेश्वर जाति कोईर निवासी ग्राम रनई तहसील पटना जिला कोरिया छ0ग0 द्वारा उपस्थित अपने स्व0प्रमिला कुमारी के मृत्यु दिनांक 09/08/2003 प्रमाण पत्र बनाने आवेदन पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया है जिस पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई।

जिस किसी हितबद्ध पक्षकार को उक्त जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में आपत्ति हो तो वह अपना आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभावक के जरिये दिनांक 18/05/2026 को उपस्थित होकर अपना आपत्ति कर सकता है, नियत तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विवाद नहीं किया जावेगा। तद्नुसार कार्यवाही कर दी जावेगी ।

आज दिनांक 07/05/2006 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय पद मुद्रा से किया गया ।

सील — तहसीलदार पटना,जिला-कोरिया

दो पन्नों में दर्ज था पूरा खेल! सट्टा कारोबारियों की सूची पहुंची अफसरों तक,कार्रवाई अब भी गायब

सूत्रों का दावा : थाना से एसपी ऑफिस तक पहुंची सट्टेबाजों की सूची, फिर भी सिस्टम खामोश

एमसीबी में कौन चला रहा सट्टा-जुआ का नेटवर्क? 19 नामों वाली सूची ने बढ़ाई हलचल

कार्रवाई से पहले लीक हो गई सूची! एमसीबी में सट्टा कारोबार पर बड़े सवाल

एक पन्ना आया सामने, दूसरा अब भी रहस्य! सट्टा-जुआ कारोबारियों की सूची से मचा हड़कंप

सूची में नाम,सिस्टम में सन्नाटा! एमसीबी के सट्टा कारोबार पर उठे गंभीर सवाल

सट्टा कारोबारियों की कथित सूची वायरल, कार्रवाई क्यों नहीं? एमसीबी पुलिस पर उठे सवाल

थानेदार से अफसर तक पहुंची जानकारी, फिर भी सट्टा कारोबार पर लगाम नहीं!

एमसीबी में 'कौन किसके संरक्षण में'? सट्टा-जुआ सूची ने खोली सिस्टम की परतें

सूत्र बोले – पन्ना अफसरों के पास, सिस्टम बोला – "देखते हैं..."

-संवाददाता-
मनेन्द्रगढ़,09 मई 2026
(घटती-घटना)।

जिले में लंबे समय से चल रहे कथित सट्टा और जुआ कारोबार को लेकर अब एक नई चर्चा ने जोर पकड़ लिया है, सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की एक हस्तलिखित सूची दैनिक घटती-घटना के हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि इस सूची में कुल 19 नाम दर्ज हैं, जिन्हें कथित रूप से जिले में संचालित सट्टा और जुए के कारोबार से जुड़ा बताया जा रहा है,सूत्रों का कहना है कि यह सूची कुल दो पन्नों में तैयार की गई थी और दोनों पन्नों में मिलाकर लगभग 30 नाम शामिल थे,हालांकि फिलहाल केवल एक पन्ना ही उपलब्ध हो सका है, जबकि दूसरा पन्ना अब तक सामने नहीं आया है,लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि यह सूची वास्तव में अधिकारियों तक पहुंच चुकी है,तो फिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

सूत्रों का दावा है की अधिकारियों की टेबल तक पहुंच चुका है पन्ना

सूत्रों के अनुसार यह सूची केवल किसी आम व्यक्ति तक सीमित नहीं रही,बल्कि जिले के कई जिम्मेदार अधिकारियों तक भी पहुंच चुकी है, सूत्रों का दावा है कि कथित सूची थाना प्रभारियों,एडिशनल एसपी और यहां तक कि एसपी कार्यालय तक भी पहुंचाई गई थी,इसके बावजूद अब तक किसी बड़े स्तर की कार्रवाई सामने नहीं आई है, यही वजह है कि अब जिले में चर्चा तेज हो गई है कि आखिर कार्रवाई किस वजह से रुकी हुई है?

दो पन्नों की सूची,लेकिन सामने केवल एक

सूत्रों के मुताबिक कुल दो पन्नों में तैयार इस कथित सूची में लगभग 30 लोगों के नाम थे,फिलहाल दैनिक घटती-घटना को केवल एक पन्ना ही उपलब्ध हो सका है,जिसमें 19 नाम दर्ज बताए जा रहे हैं,दूसरे पन्ने को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं,कुछ लोगों का कहना है कि दूसरे पन्ने में ऐसे नाम हैं जिन्हें सार्वजनिक होने से बचाया जा रहा है,वहीं कुछ लोग इसे प्रशासनिक दबाव का परिणाम बता रहे हैं, हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

हस्तलिखित सूची ने बढ़ाई हलचल

सूत्रों से मिली सूची हस्तलिखित बताई जा रही है,इसमें कई नामों के साथ कथित तौर पर उनके क्षेत्र और संचालन स्थान का भी उल्लेख किया गया है,यही वजह है कि सूची सामने आने के बाद जिले में चर्चाओं का दौर और तेज हो गया है,चाय की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया तक अब यही सवाल पूछा जा रहा है कि यदि सिस्टम को पहले से जानकारी थी,तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

टेबल तक पहुंची फाइल,लेकिन फाइलों में ही कैद कार्रवाई

जिले में व्यंग्यात्मक अंदाज में लोग अब यह कहते नजर आ रहे हैं कि एमसीबी में कार्रवाई से पहले फाइलें ज्यादा दौड़ती हैं,कहा जा रहा है कि सूची अफसरों की टेबल तक तो पहुंच गई,लेकिन कार्रवाई शायद अब भी किसी नोटशीट में अटकी हुई है,कुछ लोग यह भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि जिले में अवैध कारोबार पर कार्रवाई से पहले अनुमति का मौसम देखा जाता है।

कार्रवाई से कोसों दूर सिस्टम?

एमसीबी जिले में लंबे समय से अवैध सट्टा और जुए के कारोबार को लेकर चर्चाएं होती रही हैं, समय-समय पर पुलिस छोटे स्तर की कार्रवाई जरूर करती रही है,लेकिन सूत्रों का आरोप है कि बड़े नेटवर्क तक शायद ही कभी हाथ पहुंच पाता है,अब जब कथित सूची सामने आई है तो लोगों का सवाल और भी बड़ा हो गया है,यदि नामों की जानकारी पहले से अधिकारियों के पास थी तो क्या कार्रवाई जानबूझकर रोकी गई? क्या केवल छोटे खिलाड़ियों पर कार्रवाई होती है? क्या बड़े नामों तक पहुंचते-पहुंचते सिस्टम की रफ्तार धीमी पड़ जाती है? यही सवाल अब जिले की गलियों, चौक-चौराहों और सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं।

छोटों पर कार्रवाई,बड़े नामों पर खामोशी?

जिले में समय-समय पर पुलिस द्वारा छोटे स्तर पर जुआ और सट्टा मामलों में कार्रवाई की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन सूत्रों का आरोप है कि बड़े नेटवर्क तक कार्रवाई शायद ही कभी पहुंच पाती है,अब सूची सामने आने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या कार्रवाई केवल छोटे लोगों तक सीमित रहती है? क्या बड़े नामों तक पहुंचते-पहुंचते सिस्टम की गति धीमी पड़ जाती है? या फिर कार्रवाई किसी अदृश्य दबाव में अटक जाती है?

दैनिक घटती-घटना की पड़ताल जारी...

दैनिक घटती-घटना को सूत्रों के माध्यम से मिले इस कथित दस्तावेज की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है,समाचार पत्र केवल सूत्रों के हवाले से उपलब्ध जानकारी को सामने ला रहा है,फिलहाल अब सबकी नजर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पर टिक गई है कि क्या इस सूची को लेकर कोई जांच शुरू होगी या मामला चर्चाओं तक ही सीमित रह जाएगा,क्योंकि यदि सूची में दर्ज दावे सही हैं,तो सवाल केवल अवैध कारोबार का नहीं बल्कि कार्रवाई की निष्क्रियता का भी है।

प्रशासनिक चुप्पी बनी चर्चा का कारण

अब तक इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है,न सूची की पुष्टि की गई है और न ही उसका खंडन,यही चुप्पी अब चर्चाओं को और हवा दे रही है,यदि सूची गलत है तो उस पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं? और यदि सूची सही है तो कार्रवाई क्यों नहीं?

अब सबकी नजर पुलिस प्रशासन पर...

फिलहाल जिले की जनता की नजर पुलिस प्रशासन पर टिक गई है,लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या इस कथित सूची को लेकर कोई जांच शुरू होगी या मामला अन्य चर्चित फाइलों की तरह धीरे-धीरे ठंडे बस्ते में चला जाएगा,क्योंकि यदि सूची सही है तो सवाल कानून व्यवस्था पर है...और यदि गलत है तो सवाल अफवाह फैलाने वालों पर,लेकिन अभी तक स्थिति यही है कि सूची चर्चा में है...नाम चर्चा में हैं...और कार्रवाई अब भी चर्चा से बाहर दिखाई दे रही है।

डिस्क्लेमर

इस समाचार में प्रकाशित जानकारी सूत्रों एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रस्तुत की गई है, समाचार पत्र दैनिक घटती-घटना किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता, प्रकाशित सूची एवं उसमें दर्ज नामों की आधिकारिक पुष्टि संबंधित पुलिस अथवा प्रशासनिक विभाग द्वारा नहीं की गई है, समाचार का उद्देश्य केवल जनहित में प्राप्त सूचनाओं को सामने लाना है, यदि किसी व्यक्ति अथवा पक्ष को प्रकाशित सामग्री पर आपत्ति हो तो वह अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है,जिसे प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सूरजपुर पुलिस सख्त

219 मामलों में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कोर्ट ने लगाया 20 लाख 1 हजार रुपये का जुर्माना

-संवाददाता-
सूरजपुर,09 मई 2026
(घटती-घटना)।

जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सूरजपुर पुलिस लगातार सघन वाहन चेकिंग अभियान चला रही है,पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वालों सहित यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है,डीआईजी एवं एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत वर्ष 2026 में अब तक कुल 25,369 प्रकरणों में कार्रवाई की गई है, इन मामलों में पुलिस ने 86 लाख 65 हजार 200 रुपये का समन शुल्क वसूल किया है।

शराब पीकर वाहन चलाने पर 219 मामलों में बड़ी कार्रवाई...

पुलिस द्वारा शराब सेवन कर वाहन चलाने वालों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है,अब तक ऐसे 219 प्रकरणों में वाहन जप्त कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, इन मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा वाहन चालकों पर कुल 20 लाख 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शराब के नशे में वाहन चलाना न केवल चालक के लिए बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी गंभीर खतरा बनता है, इसी कारण ऐसे मामलों में लगातार सख्ती बरती जा रही है।

कर्मा चौक और अग्रसेन चौक में चेकिंग के दौरान पकड़े गए चालक

इसी क्रम में 6 और 7 मई 2026 को यातायात प्रभारी द्वारा कर्मा चौक और अग्रसेन चौक में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया,चेकिंग के दौरान इनोवा वाहन क्रमांक छत्र 13 AE 1810 तथा पिकअप वाहन क्रमांक CG 15 CY 6344 के चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए,पुलिस ने दोनों वाहनों को जप्त कर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई करते हुए मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां से इनोवा चालक पर 10,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वालों पर भी कार्रवाई

यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस की कार्रवाई केवल शराब पीकर वाहन चलाने तक सीमित नहीं है, जिले में अब तक बिना हेलमेट वाहन चलाने के 2,250 प्रकरण तथा बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने के भी 2,250 प्रकरण दर्ज किए गए हैं,पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ नियम तोड़ने वालों पर सख्ती भी जरूरी है।

लाइसेंस निरस्तीकरण की भी कार्रवाई

सूरजपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ केवल जुर्माना ही नहीं बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने जैसी कड़ी कार्रवाई भी कराई जा रही है, पुलिस का कहना है कि लापरवाही से वाहन चलाने वाले चालक सड़क दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बनते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

सूरजपुर पुलिस की अपील

सूरजपुर पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और शराब सेवन के बाद वाहन चलाने से बचें, पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा जनहित से जुड़ा विषय है और हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह सुरक्षित यातायात व्यवस्था में सहयोग करे, पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि सड़क हादसों को रोकने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी, इस अभियान में जिले के सभी थाना एवं चौकी की पुलिस टीमों ने सक्रिय और समन्वित भूमिका निभाई।

CMYK

पटना नगर पंचायत में टेंडर नहीं,महायज्ञ चल रहा है!

60 लाख के काम पर ऐसा प्रेम, टेंडर खुलने से पहले ठेकेदार तय!

29 अप्रैल को खुलना था टेंडर, अब तक चल रही 'मैनेजमेंट प्रक्रिया'

पटना नगर पंचायत में विकास कम, सेटिंग ज्यादा तेज

12 ने डाला टेंडर, काम फिर भी एक तयशुदा ठेकेदार का?

सीसी सड़क और चेकर टाइल्स से ज्यादा मजबूत दिख रही सेटिंग

टेंडर रुका है या कमीशन का गणित अभी बाकी है?

नगर पंचायत पटना में टेंडर खोलने से पहले ठेकेदारों का शुद्धिकरण अभियान

टेंडर खुलने से पहले ही विजेता की चर्चा, आखिर अंदरखाने चल क्या रहा है?

60 लाख के काम पर ऐसी साधना कि 29 अप्रैल से टेंडर आज तक ध्यान मुद्रा में बैठा है?

29 अप्रैल को खुलना था टेंडर... पर टेंडर ने भी कहा...अभी नहीं

सरकारी कागजों के अनुसार टेंडर 29 अप्रैल को खुलना था,तारीख आई, लोग इंतजार में बैठे, ठेकेदारों ने फाइलें संभालीं,कुछ ने मिठाई तक का इंतजाम कर लिया होगा,लेकिन टेंडर नहीं खुला,अब 9 मई तक भी टेंडर नहीं खुल पाया, नगर में लोग पूछ रहे हैं क्या टेंडर की चाबी खो गई? या फिर सिस्टम अभी ग्रह-नक्षत्र देख रहा है? लेकिन सूत्रों की मानें तो मामला ग्रह-नक्षत्र का नहीं, सेटिंग नक्षत्र का है, चर्चा यह है कि जिस ठेकेदार को काम मिलना तय माना जा रहा है, उसकी पूरी व्यवस्था अभी फाइनल नहीं हो पाई थी, इसलिए टेंडर भी तब तक समाधि में चला गया जब तक सभी ग्रह एक लाइन में न आ जाएं।

विकास कार्य नहीं,पूर्व निर्धारित कार्यक्रम

स्थानीय चर्चा तो यहां तक कह रही है कि यह टेंडर प्रक्रिया नहीं,बल्कि पहले से लिखा गया स्क्रीनप्ले है। कलाकार तय हैं,डायलॉग तय हैं, बस जनता को यह महसूस कराया जा रहा है कि मुकाबला बहुत कड़ा है, बताया जा रहा है कि करीब 12 लोगों ने टेंडर डाला है, अब 12 लोगों ने टेंडर क्यों डाला, यह अलग विषय है, लेकिन नगर में यह चर्चा ज्यादा जोर पकड़ रही है कि अब उन 12 में से कितनों को समझाया जाएगा, किसी को सम्मानपूर्वक बाहर किया जाएगा, किसी को आर्थिक राष्ट्रनिर्माण में सहयोग का अवसर दिया जाएगा, और जो फिर भी नहीं मानेगा, उसके लिए लोकतंत्र का सबसे पुराना फार्मूला तैयार है — साम, दाम, दंड, भेद।

5 प्रतिशत त्यागियों को,10 प्रतिशत सिस्टम को!

नगर की राजनीतिक और ठेकेदारी गलियों में इन दिनों गणित भी खूब चल रहा है, सूत्रों के हवाले से ऐसी चर्चाएं हैं कि जो लोग टेंडर से पीछे हट जाएंगे, उनके लिए लगभग 5 प्रतिशत सम्मान राशि की व्यवस्था हो सकती है, अब इसे त्यागपत्र सम्मान कहें या प्रतियोगिता छोड़ो प्रोत्साहन योजना — यह समझना कठिन है,इसके बाद चर्चा यह भी है कि करीब 10 प्रतिशत सिस्टम में जाएगा, यानी विकास कार्य शुरू होने से पहले ही विकास राशि का आध्यात्मिक विभाजन प्रारंभ हो चुका है। सड़क अभी बनी नहीं,लेकिन कमीशन की सड़कें पहले ही चार लेन हो चुकी हैं।

-रवि सिंह-
पटना/कोरिया,09 मई 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले के इकलौते नगर पंचायत पटना में इन दिनों विकास कार्य कम और व्यवस्थित विकास ज्यादा चर्चा में है,नगर पंचायत में लगभग 60 लाख रुपये के सीसी सड़क और चेकर टाइल्स निर्माण कार्य का टेंडर ऐसा रहस्यमयी अध्याय बन चुका है, जिसे समझने के लिए शायद इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि तंत्र-मंत्र और राजनीतिक ज्योतिष की जरूरत पड़ जाए, कहने को यह सिर्फ एक सामान्य टेंडर प्रक्रिया है, लेकिन नगर में चर्चा ऐसे हो रही है मानो कोई राजतिलक होना हो और पूरा राज्य उसी की तैयारी में जुटा हो, फर्क सिर्फ इतना है कि यहां सिंहासन की जगह ठेका है और राजमुकुट की जगह वर्क ऑर्डर।

डिजिटल सिग्नेचर का 'रहस्य' और 60 लाख का टेंडर

पटना नगर पंचायत में 60 लाख रुपये के सीसी सड़क और चेकर टाइल्स निर्माण कार्य से जुड़ा टेंडर अब सिर्फ निर्माण कार्य नहीं,बल्कि रहस्यों का केंद्र बनता जा रहा है, पहले टेंडर निर्धारित तारीख 29 अप्रैल को नहीं खुला और अब इसके पीछे डिजिटल सिग्नेचर की कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है,नगर में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी से पहले इंजीनियर पदस्थ हो गए, कार्यालय संभाल लिया,लेकिन आज तक उनका डिजिटल सिग्नेचर तैयार नहीं हो पाया, बताया जा रहा है कि 29 अप्रैल को टेंडर खोला जा सकता था,लेकिन ऐन वक्त पर यह जानकारी दी गई कि इंजीनियर के पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है,इसलिए वे प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा सकते, दूसरी ओर मुख्य नगर पालिका अधिकारी के बाहर होने की बात कही गई,अब सवाल यह उठ रहा है कि जब टेंडर प्रक्रिया पहले से तय थी,तब डिजिटल सिग्नेचर जैसी अनिवार्य व्यवस्था समय पर क्यों नहीं की गई? क्या यह केवल तकनीकी लापरवाही है या फिर इसके पीछे कोई सुविधाजनक देरी छिपी हुई है? नगर में इस बात की भी चर्चा है कि यदि इंजीनियर के पास अधिकारिक डिजिटल सिग्नेचर नहीं था तो फिर टेंडर प्रक्रिया की पूरी जिम्मेदारी किस व्यवस्था के भरोसे चल रही थी,लोग व्यंग्य में कह रहे हैं कि यहां सड़क निर्माण से पहले डिजिटल सिग्नेचर का निर्माण जरूरी हो गया है,अब नगर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर टेंडर प्रक्रिया को नियंत्रित कौन कर रहा है—तकनीकी व्यवस्था, प्रशासनिक मजबूरी या फिर पर्दे के पीछे चल रही कोई और सेटिंग?

अब सबकी नजर अंतिम परिणाम पर...

फिलहाल पटना नगर पंचायत का यह 60 लाख वाला टेंडर पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है, अब देखना यह है कि जब टेंडर खुलेगा तो क्या वही नाम सामने आएगा जिसकी चर्चा पहले से चल रही है,या फिर प्रशासन सभी आरोपों को गलत साबित करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया का उदाहरण पेश करेगा,लेकिन फिलहाल नगर में एक ही चर्चा है,टेंडर खुले न खुले,सेटिंग पूरी होनी चाहिए।

आखिर वह ठेकेदार कौन है?

नगर में इन दिनों एक नाम हवा में तेजी से तैर रहा है कोई देवाशीष है, चर्चा यह है कि काम उसी को मिलना लगभग तय माना जा रहा है, लोग अब मजाक में पूछने लगे हैं जब सब तय है तो टेंडर की जरूरत क्या थी? किसी ने तो यहां तक कह दिया सीधे बोर्ड लगा देते, यह काम पहले से आरक्षित है, कृपया बाकी ठेकेदार अपना समय और डीजल बचाएं,हालांकि आधिकारिक रूप से अब तक कुछ घोषित नहीं हुआ है,लेकिन नगर में जिस आत्मविश्वास के साथ नाम लिया जा रहा है,उससे लोग हैरान जरूर हैं।

नगर पंचायत में एकता का अद्भुत उदाहरण

देश में जहां राजनीतिक दलों,विभागों और अधिकारियों में अक्सर मतभेद देखने को मिलते हैं, वहीं पटना नगर पंचायत ने एक नई मिसाल पेश कर दी है, यहां चर्चा है कि प्रतिनिधि और अधिकारी सभी एकजुट हैं, इतनी एकजुटता तो शायद नगर विकास योजनाओं में भी कभी नहीं दिखी होगी, सड़क, पानी, सफाई और नाली के मुद्दों पर भले मतभेद हो जाएं, लेकिन कौन ठेकेदार अपना है इस मुद्दे पर कथित तौर पर सभी का सामूहिक चिंतन जारी है।

टेंडर नहीं खुल रहा या मैनेजमेंट प्रक्रिया चल रही है?

नगर के जानकारों का कहना है कि यदि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है तो फिर निर्धारित तिथि के बाद भी टेंडर क्यों नहीं खोला गया? क्या कोई तकनीकी कारण है? क्या कोई प्रशासनिक आदेश लंबित है? या फिर वास्तव में अंदरखाने वही सब चल रहा है जिसकी चर्चा चाय दुकानों से लेकर कार्यालयों तक हो रही है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि टेंडर प्रक्रिया निष्पक्ष है तो उसकी स्थिति सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही?

जनता भी अब समझदार हो गई है...

पहले लोग सोचते थे कि सड़क बन रही है तो विकास हो रहा है। अब लोग समझने लगे हैं कि सड़क बनने से पहले कितनी राजनीतिक इंजीनियरिंग और आर्थिक वास्तुशास्त्र काम करता है, नगर में लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि सड़क की मोटाई बाद में नापी जाएगी, पहले कमीशन की गहराई मापी जा रही है।

डीआईजी/एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को किया रवाना

विश्रामपुर क्षेत्र में 24 घंटे सक्रिय रहेगी सेवा,जल्द जिले को मिलेंगी 12 और गाड़ियां

सूरजपुर जिले में डॉयल 112 सेवा का ट्रायल शुरू

-संवाददाता-
सूरजपुर,09 मई 2026 (घटती-घटना)।

जिले में पुलिस व्यवस्था को और अधिक तेज, प्रभावी एवं आमजन के लिए सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है, दुर्घटना, आपात स्थिति अथवा किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता के लिए अब लोगों को त्वरित मदद उपलब्ध कराने हेतु जिले में डॉयल 112 सेवा का ट्रायल प्रारंभ कर दिया गया है, सी-4 रायपुर से जिले को प्रारंभिक ट्रायल के लिए डॉयल 112 का एक वाहन प्राप्त हुआ है, जिसका कोड विश्रामपुर-अरपा-1 रखा गया है, यह वाहन विश्रामपुर क्षेत्र में 24 घंटे सातों दिन लगातार सक्रिय रहकर लोगों को त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराएगा, शुक्रवार 08 मई 2026 को जिले के डीआईजी एवं एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने पुलिस लाइन परिसर में डॉयल 112 वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस दौरान डीआईजी/एसएसपी ने कहा कि डॉयल 112 सेवा शुरू होने से पुलिस रिस्पॉन्स सिस्टम पहले से अधिक मजबूत होगा और पीड़ितों को समय पर सहायता मिल सकेगी,उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में जिले के सभी थाना क्षेत्रों के लिए डॉयल 112 की 12 और गाड़ियां प्राप्त होंगी, जिसके बाद पूरे जिले में यह सेवा सुचारू रूप से संचालित की जाएगी, उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं, आपराधिक घटनाओं तथा आपात स्थितियों में पुलिस की प्रतिक्रिया समय को काफी कम किया जा सकेगा, इससे आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना और अधिक मजबूत होगी,कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश देवांगन, एसडीओपी ओड़गी राजेश जोशी, डीएसपी अनूप एक्का, रीना नीलम कुजूर, डीएसपी मुख्यालय महालक्ष्मी कुलदीप सहित जिले के थाना एवं चौकी प्रभारी उपस्थित रहे, पुलिस अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि डॉयल 112 सेवा शुरू होने से आम लोगों को त्वरित सहायता मिलेगी और कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

सूने मकान में लाखों की चोरी,बेटियों के जेवर और नकदी ले उड़े चोर

महंगवा वार्ड में बड़ी वारदात से दहशत,पांच ताले तोड़कर घर में घुसे बदमाश,करीब 20 लाख की चोरी से परिवार सदमे में...शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

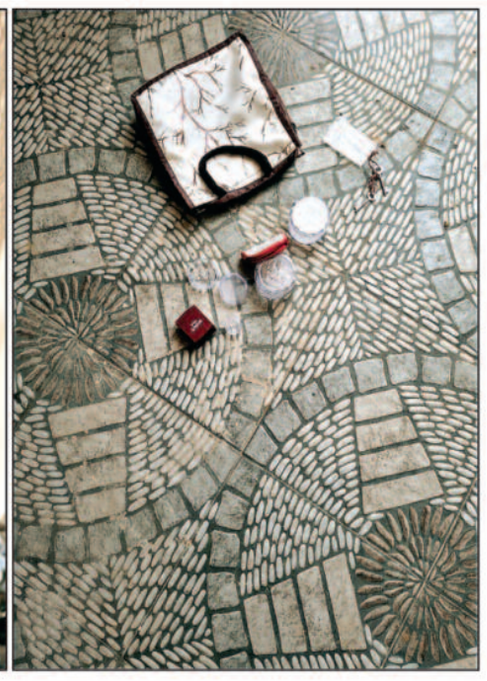

-संवाददाता-
सूरजपुर,09 मई 2026 (घटती-घटना)।

शहर के महंगवा वार्ड क्रमांक 02 में अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपये की चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। घटना में चोर घर से करीब 15 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात और लगभग 5 लाख रुपये नकद लेकर फरार हो गए, घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है,वहीं लोगों में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है।

जानकारी के अनुसार महंगवा वार्ड निवासी जाकिर हुसैन पेशे से ठेकेदारी एवं पेटी कॉन्ट्रैक्टर का कार्य करते हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार को वे अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने बाहर गए हुए थे। घर पूरी तरह सूना था और मकान में ताला बंद था, शुक्रवार सुबह पड़ोसियों ने उन्हें फोन कर सूचना दी कि उनके घर के कुछ दस्तावेज बाहर बिखरे पड़े हैं, सूचना मिलने के बाद जब जाकिर हुसैन अपने घर पहुंचे तो मुख्य दरवाजे सहित कुल पांच ताले टूटे हुए मिले, घर के अंदर का नजारा देखकर परिवार के होश उड़ गए,तीनों अलमारियों के लॉक टूटे पड़े थे और सामान बिखरा हुआ था,पीड़ित परिवार के अनुसार अज्ञात चोर उनकी तीनों बेटियों के शादी के लिए रखे गए करीब 15 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात और लगभग 5 लाख रुपये नकद चोरी कर ले गए, घटना के बाद परिवार गहरे सदमे में है, परिवार का कहना है कि बेटियों के भविष्य और शादी के लिए वर्षों से धीरे-धीरे जोड़कर रखे

पुलिस जांच में जुटी,लेकिन लोगों के सवाल बरकरार

मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया,पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है,पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने, संदिग्ध लोगों से पूछताछ करने और पुराने अपराधियों की गतिविधियों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है,हालांकि शहर के बीचों-बीच हुई इस बड़ी चोरी की घटना ने पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं,स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं,लेकिन रात में पुलिस पेट्रोलिंग प्रभावी नजर नहीं आती। लोगों का आरोप है कि यदि नियमित गश्त होती तो शायद इतनी बड़ी वारदात को रोका जा सकता था।

ताले टूटते रहे और सिस्टम सोता रहा?

घटना के बाद इलाके में लोग व्यंग्यात्मक अंदाज में यह कहते नजर आए कि चोर आराम से पांच ताले तोड़ते रहे और सुरक्षा व्यवस्था शायद गहरी नींद में थी,लोगों का कहना है कि शहर में चोरी की घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन अपराधियों में पुलिस का खौफ कम दिखाई दे रहा है,कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर मुख्य आबादी वाले इलाके में इतनी बड़ी वारदात बिना किसी हलचल के कैसे हो गई?

अब खुलासे का इंतजार...

फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि पुलिस इस सनसनीखेज चोरी का खुलासा कब तक कर पाती है, क्योंकि इस घटना में केवल नकदी और जेवर की चोरी नहीं हुई है, बल्कि एक परिवार की वर्षों की मेहनत और बेटियों के भविष्य से जुड़ी उम्मीदें भी अपराधियों ने लूट ली हैं।

CMYK

सुशासन अब दफ्तरों में नहीं,गांव की चौपाल तक : मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल

सुशासन तिहार 2026 में जनसमस्याओं का मौके पर समाधान,मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बोले...सरकार सीधे जनता के बीच पहुंच रही

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां,09 मई 2026 (घटती-घटना)। 'गांव-गांव, द्वार-द्वार सुशासन तिहार 2026' के तहत विकासखंड खड़गवां के ग्राम मझौली में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में ग्रामीणों की भारी भागीदारी देखने को मिली, शिविर में 10 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण अपनी समस्याएं और आवेदन लेकर पहुंचे, जहां विभिन्न विभागों द्वारा मौके पर ही समस्याओं केसमाधान की व्यवस्था की गई, कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, शिविर परिसर में सुबह से ही ग्रामीणों की भीड़ उमड़ने लगी थी, अलग-अलग विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, जहां अधिकारी सीधे आम लोगों से आवेदन लेकर उनका निराकरण कर रहे थे। बता दे की खड़गवां में आयोजित 'सुशासन तिहार 2026' का यह शिविर प्रशासन और जनता के बीच संवाद का बड़ा मंच बनकर सामने आया, सरकार की मंशा योजनाओं को सीधे गांव तक पहुंचाने और समस्याओं का मौके पर समाधान करने की दिखाई दी, अब देखना यह होगा कि शिविर में प्राप्त शेष आवेदनों का निराकरण कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से किया जाता है।

सरकार अब जनता के द्वार पर...

राज्य सरकार द्वारा 1 मई से 10 जून तक चलाए जा रहे 'सुशासन तिहार 2026' अभियान का उद्देश्य शासन की योजनाओं का लाभ सीधे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान करना है, शिविर में एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं, इस दौरान कुल 392 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कई मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया। ग्रामीणों ने राशन कार्ड,वन अधिकार पट्टा, आयुष्मान कार्ड, जॉब कार्ड और अन्य योजनाओं से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं।

हितग्राहियों को मिला योजनाओं का लाभ

शिविर में पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ भी वितरित किए गए। कई लोगों को राशन कार्ड,आयुष्मान कार्ड और जॉब कार्ड उपलब्ध कराए गए, जबकि वन अधिकार पट्टों का वितरण भी किया गया,ग्रामीणों ने मौके पर समाधान मिलने पर संतोष जताया और कहा कि पहले छोटी-छोटी समस्याओं के लिए कई बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे,लेकिन शिविर के माध्यम से राहत मिली है।

मंत्री जायसवाल बोले... जनसेवा को मजबूत कर रही सरकार

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार अब केवल दफ्तरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव-गांव पहुंचकर जनता की समस्याएं सुन रही है, उन्होंने कहा कि 'सुशासन तिहार' केवल एक सरकारी अभियान नहीं बल्कि सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का माध्यम है, मंत्री ने कहा कि इस अभियान के जरिए पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसेवा को मजबूत किया जा रहा है ताकि आम लोगों को छोटी समस्याओं के लिए भटकना न पड़े, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्राप्त शिकायतों और आवेदनों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

ग्रामीणों में दिखा उत्साह

कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण,महिला समूह, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। शिविर में कई लोगों ने अपनी व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं, ग्रामीणों का कहना था कि इस प्रकार के शिविरों से प्रशासन और जनता के बीच दूरी कम होती है तथा लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ दोनों मिलते हैं।

जनसमस्याओं के समाधान पर जोर

शिविर में पेयजल, सड़क, राजस्व प्रकरण, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, वन अधिकार, रोजगार और राशन वितरण से जुड़े कई मामलों पर सुनवाई की गई, अधिकारियों ने लोगों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी जोर दिया।

मनोरंजन समाचार

बॉक्स ऑफिस पर तारा सिंह का चलेगा ढाई किलो का हाथ

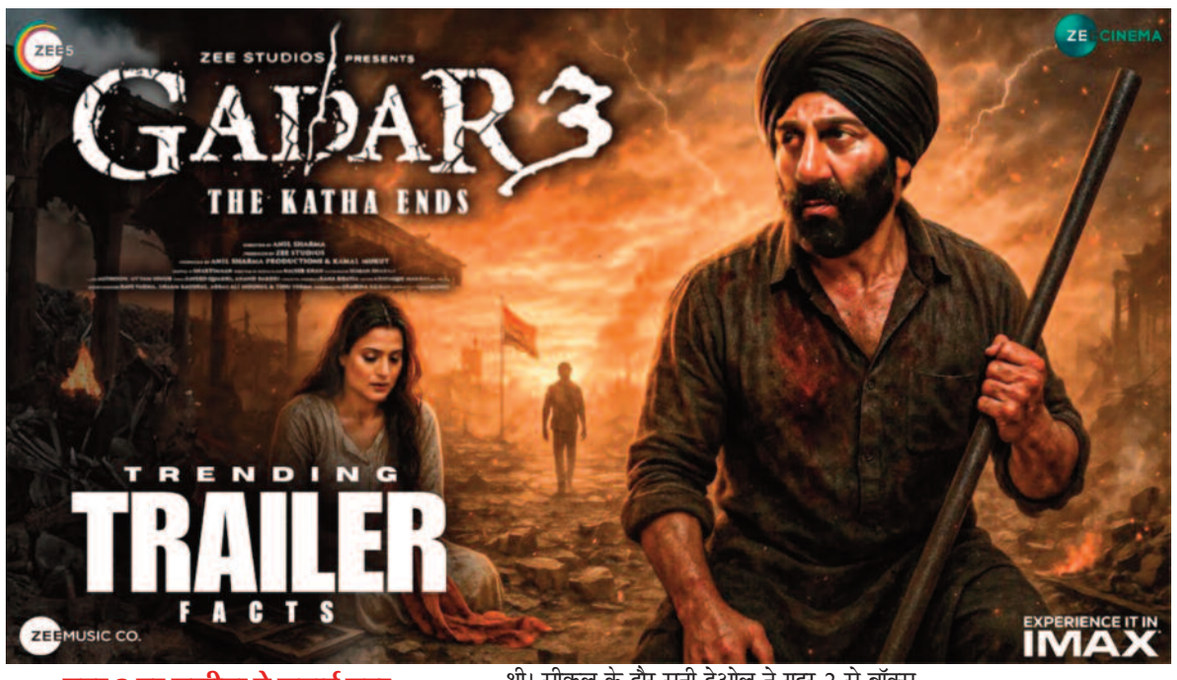

गदर 3 पर सकीना ने लगाई मुहर

गदर 2 की सफलता के बाद अब गदर 3 से सनी देओल और अमीषा पटेल धमाल मचाने जा रही हैं। फिल्म पर मुहर लग गई है।फिर से बड़े पर्दे पर तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी लौट रही है। गदर और गदर 2 की जबरदस्त सफलता के बीच आखिरकार गदर 3 पर भी बड़ा अपडेट आ गया है।लंबे समय से गदर 3 को लेकर चर्चा हो रही थी। सीक्वल के दौर सनी देओल ने गदर 2 से बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया था। गदर 2 दो दशक के बाद सिनेमाघरों में आई थी और फिर भी क्रेज पुराने जैसा था।

लौट रहे तारा सिंह और सकीना

गदर 2 की सफलता के बाद दर्शक गदर 3 का इंतजार कर रहे थे जो अब आखिरकार पूरा होने वाला है। जी हां, गदर 3 पर मुहर लगा दी गई है और यह काम किसी और ने नहीं बल्कि फिल्म की सकीना उर्फ अमीषा पटेल ने किया है।

गदर 3 पर अमीषा पटेल ने लगाई मुहर

अमीषा पटेल ने एक एक्स पोस्ट के जरिए गदर 3 पर मुहर लगाई है और दावा किया है कि यह फिल्म मिनिमम 500 करोड़ तो कमाएगी ही कमाएगी। एक्ट्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा-गदर 3 जरूर आएगी और जब आएगी तो ऑडियंस के प्यार और भगवान की दुआओं से थिएटर्स में हंगामा मच जाएगा। गदर 3 जैसे ब्रांड के लिए बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये तो मिनिमम कलेक्शन होने वाला है। इस बार स्केल बड़ा होगा और स्क्रिप्ट पहले से ज्यादा बड़ी और धमाकेदार होगी। गदर 3 को लेकर अमीषा पचेल के इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। फैंस अपनी एक्साइटमेंट नहीं रोक पा रहे हैं। अब देखते हैं कि मेकर्स फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब करते हैं। फिल्म के दोनों पार्ट अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था।

गदर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बता दें कि साल 2023 में रिलीज हुई गदर 2 से सनी देओल और अमीषा पटेल ने सालों बाद कमबैक किया था। उनकी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 525.45 करोड़ और दुनियाभर में 691.08 करोड़ रुपये कमाए थे।

मेरे जख्म मेरी कहानी बयां करते हैं : राजश्री देशपांडे

टीवी और फिल्म अभिनेत्री राजश्री देशपांडे ने ब्रेस्ट कैंसर से अपनी लड़ाई और जीत की कहानी को बेहद साहस के साथ सोशल मीडिया पर साझा किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें उन्होंने अपने शरीर पर बचे सर्जरी के निशानों को खुलकर दिखाया और उन्हें अपनी ताकत व हिम्मत का प्रतीक बताया। इंडस्ट्री में जहां दिखावे और परफेक्शन को बहुत महत्व दिया जाता है, राजश्री देशपांडे ने सच्चाई और साहस को चुनते हुए एक मजबूत संदेश दिया है। इंस्टाग्राम पर किए पोस्ट में राजश्री ने लिखा, मेरे जख्म मेरी जिंदगी की कहानी बयां करते हैं। हर एक जख्म इस बात की याद दिलाता है कि मैंने लड़ाई लड़ी, मैं जिंदा बची और मैंने जीत हासिल की। उन्होंने आगे लिखा, ब्रेस्ट कैंसर ने अपने निशान तो छोड़े, लेकिन वह कभी भी मेरी हिम्मत को छू नहीं पाया। हर उस महिला से, जो अपनी चमक को फीका कर रही है प्लीज उठो। तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारे जख्म कोई दाग नहीं हैं, बल्कि वे तुम्हारे साहस का ताज हैं। राजश्री देशपांडे ने कहा कि आज वे अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी हैं। उनके दिल में प्यार है और रूह में हिम्मत। उन्होंने सभी महिलाओं को संदेश दिया कि जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए और अपने जख्मों को शर्मिंदगी की जगह ताकत बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। राजश्री की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी सराही जा रही है। कई महिलाएं और सेलिब्रिटी उनकी हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने मैसेज दिया है कि सौंदर्य सिर्फ बाहरी दिखावे में नहीं,बल्कि अंदर की ताकत और साहस में छिपा होता है। उन्होंने अपने संघर्ष को खुलकर साझा करके कई महिलाओं को हौसला दिया है। राजश्री की पोस्ट पर दिया मिर्जा,अमृता खानविलकर,शुभांगी लाटकर,शिल्पा तुलस्कर समेत कई सितारे व सोशल मीडिया यूजर्स भी खुलकर उनकी तारीफ करते नजर आए।

खेल समाचार

तेजिंदरपाल सिंह तूर ने इंडियन एथलेटिक्स सीरीज़ के संगरूर चरण में शॉट पुट का खिताब जीता

संगरूर,09 मई 2026। पुरुषों के शॉट पुट में दो बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता, तेजिंदरपाल सिंह तूर ने शनिवार को पंजाब के संगरूर में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज़ के पांचवें चरण में शानदार प्रदर्शन किया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने इस इवेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो 19.97 मीटर दर्ज किया और शानदार जीत हासिल की। पंजाब के 31 वर्षीय अनुभवी थ्रोअर इस महीने के अंत में रांची में होने वाली आगामी प्रमुख घरेलू प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे हैं। 2018 और 2022 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले तेजिंदरपाल सिंह तूर ने कहा, इस सीज़न का मुख्य लक्ष्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के शिखर पर पहुंचना है। तूर का इस सीज़न का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 21.03 मीटर था, जो अप्रैल की शुरुआत में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज़ के दिल्ली चरण में दर्ज किया गया था।एक दिवसीय इंडियन एथलेटिक्स सीरीज़ का संगरूर चरण, महिलाओं की भाला फेंक (जेवलिन थ्रो) में दो बार की ओलंपियन और एशियाई खेलों की चैंपियन अन्नू रानी के लिए भी, आगे आने वाले चुनौतीपूर्ण सीज़न के लिए अपनी तैयारियों को परखने का एक अच्छा मौका था। 33 वर्षीय अन्नू ने शनिवार को 55.78 मीटर के थ्रो के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।

महिलाओं की भाला फेंक के एक रोमांचक मुकाबले में, हरियाणा की शिल्पा रानी पहले स्थान पर रहीं (57.65 मीटर), जबकि आंध्र प्रदेश की रश्मि के ने दूसरा स्थान हासिल किया (56.15 मीटर)। संगरूर में आयोजित इस एक दिवसीय प्रतियोगिता में, एयर फोर्स के हरजीत सिंह और त्रिपुरा की फातिमा बेगम क्रमशः पुरुषों और महिलाओं की दौड़ में सबसे तेज़ धावक बनकर उभरे। फातिमा ने महिलाओं की 200 मीटर दौड़ भी जीती।

जोफा आर्चर ने फेंका आईपीएल इतिहास का सबसे लंबा ओवर,

जयपुर,09 मई 2026। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला एक ऐसे रिकॉर्ड के साथ शुरू हुआ जिसकी कल्पना खुद मेजबान टीम ने भी नहीं की होगी। राजस्थान के स्टार तेज गेंदबाज जोफा आर्चर ने इस सीजन अपनी रफ्तार के लिए तो सुर्खियां बटोरीं लेकिन साथ ही आईपीएल इतिहास का सबसे लंबा पहला ओवर फेंकने का अनचाहा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। आर्चर का यह शुरुआती ओवर पूरे 11 गेंदों तक चला जिसने गुजरात टाइटंस को मैच की शुरुआत में ही बड़ी बढ़त दिला दी।

पहली गेंद से लय में नहीं आए नजर

अपनी सटीक गेंदबाजी और घातक बाउंसर के लिए मशहूर आर्चर आज लय हासिल करने के लिए जूझते नजर आए। ओवर की शुरुआत से ही उनका नियंत्रण उनके साथ नहीं था। पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन ने पॉइंट के ऊपर से चौका जड़कर इरादे साफ कर दिए। इसके बाद आर्चर ने एक के बाद एक कई वाइड और नो-बॉल फेंककर न सिर्फ बल्लेबाजों का काम आसान किया बल्कि अपनी टीम के कप्तान यशस्वी जायसवाल की चिंताएं भी बढ़ा दीं।

केएल राहुल ने रचा इतिहास

3 टीमों से 1,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने

नईदिल्ली,09 मई 2026। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 51वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। दरअसल, राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए 1,000 रन पूरे कर लिए। वह लीग इतिहास में 3 टीमों से 1,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। मैच में वह 14 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हुए। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने आईपीएल में 500 चौके भी पूरे किए।

राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए पहला मुकाबला आईपीएल 2025 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 24 मैच खेले हैं और इसकी 24 पारियों में 50.35 की औसत से 1,007 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 162.41 की रही है। उनके बल्ले से 2 शतक और 6 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 152* रन है। राहुल दिल्ली कैपिटल्स के लिए 1,000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले 11वें बल्लेबाज हैं।

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए राहुल ने 38 पारियों में 41.47 की औसत और 130.67 की स्ट्राइक रेट से 1,410 रन बनाए थे। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए राहुल से ज्यादा रन सिर्फ निकोलस पूरन (1,564 रन) ने बनाए हैं। पंजाब किंग्स के लिए राहुल ने 55 मैचों की 55 पारियों में 56.62 की औसत और 139.76 की स्ट्राइक रेट से 2,548 रन बनाए थे। राहुल पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं।

आईपीएल में सबसे ज्यादा चौके विराट कोहली ने लगाए हैं। उनके बल्ले से 813 चौके निकले हैं। शिखर धवन दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 768 चौके लगाए हैं। डेविड वार्नर ने 663 और रोहित शर्मा ने 659 चौके जड़े हैं। अजिंक्य रहाणे 526 चौके के साथ 5वें और सुरेश रैना 506 चौकों के साथ छठे स्थान पर हैं। राहुल 500 चौके के साथ 7वें स्थान पर हैं। राहुल ने आईपीएल 2026 में 11 पारियों में 468 रन बनाए हैं।

राहुल ने अपना पहला मुकाबला 2013 में खेला था। उन्होंने अब तक 156 मुकाबले खेले हैं और इसकी 147 पारियों में 46.26 की औसत और 138.81 की स्ट्राइक रेट से 5,690 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 6 शतक और 43 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 152* रन रहा है। इस खिलाड़ी ने लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के लिए भी 1,000 से ज्यादा आईपीएल रन बनाए हैं।

एलपीजी गैस घोटाला...पूर्व राज्यमंत्री का दामाद एजेंसी संचालक अरेस्ट

खाद्य अधिकारी-व्यापारी भी गिरफ्तार,ठाकुर पेट्रोकेमिकल ने 1.5 करोड़ की गैस निकालकर बेची थी...

महासमुंद,09 मई 2026। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स कंपनी के मालिक ने 1.5 करोड़ रुपए की एलपीजी गैस चुराई। दिसंबर 2025 में पुलिस ने 90 मीट्रिक टन एलपीजी ले जा रही 6 गैस कैप्सूल गाड़ियों को जब्त किया था। लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण सभी गाड़ियां थाने में खड़ी कर दी गई। अब पुलिस ने तीनों मुख्य आरोपियों अजय यादव (जिला खाद्य अधिकारी), मनीष चौधरी (व्यापारी) और पंकज चंद्राकर (एजेंसी संचालक) को गिरफ्तार कर लिया है। पंकज पूर्व राज्य मंत्री पूनम चंद्राकर के बड़े भाई धन्नजय चंद्राकर का दामाद है। ठाकुर पेट्रोकेमिकल के मालिक संतोष ठाकुर और सार्थक ठाकुर फरार हैं। जिनकी तलाश की जा रही है।

प्लानिंग के साथ 6 गैस कैप्सूल किए 'हैंडओवर'

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि, खाद्य अधिकारी अजय यादव, व्यापारी मनीष चौधरी और गौरव गैस एजेंसी के संचालक पंकज चंद्राकर ने एक सोची-समझी साजिश रची थी।

ठाकुर पेट्रोकेमिकल के मालिक फरार

पुलिस को इस पूरे खेल में अभनपुर के ठाकुर पेट्रोकेमिकल के संचालकों की संलिप्तता के पुख्ता सबूत मिले हैं। हालांकि, पुलिस की दबिश से पहले ही फर्म के मालिक संतोष ठाकुर और सार्थक ठाकुर फरार हो गए हैं। पुलिस की टीमें उनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं।

इन्होंने गैस से भरे 6 बड़े कैप्सूल (टैंकर) को सीधे अभनपुर स्थित ठाकुर पेट्रोकेमिकल को सौंप दिया। बाजार में इस गैस की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है।

बता दें कि गौरव गैस एजेंसी भाजपा के पूर्व राज्यमंत्री पूनम चंद्राकर के बड़े भाई धन्नजय चंद्राकर का है। पंकज चंद्राकर धनंजय चंद्राकर का दामाद है।

जानकारी के अनुसार, दिसंबर 2025 में सिंघोड़ा थाना पुलिस ने 6 एलपीजी गैस से भरे कैप्सूल ट्रक जब्त किए गए थे। थाने में किसी भी हादसे के खतरा देखते हुए, इन ट्रकों को सुरक्षित जगह पर रखने के लिए महासमुंद पुलिस ने जिला कलेक्टर को पत्र भेजा। इसके बाद कलेक्टर ने खाद्य विभाग को ट्रकों को सुरक्षित जगह पर रखने के निर्देश दिए। इसी आदेश के तहत 30 मार्च 2026 को खाद्य विभाग की टीम ने ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स के मालिक संतोष सिंह ठाकुर से संपर्क किया और 6 कैप्सूल ट्रक सुरक्षित रखने के लिए कहा। खाद्य निरीक्षक अविनाश दुबे, खाद्य अधिकारी हरिश सोनेश्वरी और मनीष चौधरी की मौजूदगी में संतोष ठाकुर को ये 6 कैप्सूल ट्रक सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिए। संतोष अपने स्टाफ की मदद से सभी गाड़ियां सिंघोड़ा थाना से रायपुर के अभनपुर के ग्राम उरला स्थित अपने प्लांट ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स ले गया।

कंपनी के मालिक ने गैस बेचने की प्लानिंग की...

हैंडओवर के समय या उसके तुरंत बाद कैप्सूल ट्रकों का वजन नहीं कराया गया। इसी लापरवाही का फायदा उठाकर मालिक संतोष ठाकुर (56), डायरेक्टर सार्थक ठाकुर ने गैस को अवैध रूप से बेचने की प्लानिंग की। सिंघोड़ा से अभनपुर तक लगभग 200 किलोमीटर के रास्ते में 15 से ज्यादा धर्मकांटे (वजन करने की जगह) होने के बावजूद कहीं भी वजन नहीं कराया गया। सभी 6 कैप्सूल ट्रकों को प्लांट से करीब 200 मीटर दूर पार्किंग में खड़ा कर दिया गया। इसके बाद 5 गाड़ियों का वजन 6 अप्रैल को और 1 गाड़ी का वजन 8 अप्रैल को कराया गया।

8 दिनों में प्लांट के बुलेट टैंकों में खाली किया गैस

इन 8 दिनों में एक-एक कर कैप्सूल ट्रकों को प्लांट के अंदर मौजूद बुलेट टैंकों में खाली किया गया। जब वे टैंक भी भर गए तो गैस को कंपनी के मालिकाना और वहां चल रहे दो निजी टैंकरों में भर दिया गया। इसके बावजूद चोरी की गई गैस बची रह गई, जो तय क्षमता से ज्यादा थी। इसके बाद रायपुर की अलग-अलग एजेंसियों और प्लांटों को करीब 4 से 6 टन गैस बिना पक्के बिल के, सिर्फ कच्चे चालान पर भेजी गई। वजन में देरी का मुख्य कारण यह रहा कि कैप्सूल ट्रकों को समय पर खाली नहीं किया गया और प्लांट में एक साथ 6 कैप्सूल खाली करने की कैपेसिटी भी नहीं थी। इसके बाद कंपनी मालिक ने प्रशासन को बताया कि सभी एलपीजी कैप्सूल ट्रक खाली हैं। इसके बाद जब पुलिस ने मामले की जांच की तो पूरा घोटाला सामने आया।

कार के कुचलने से 3 दोस्तों की मौत

बालोद में हादसा...टक्कर से उछलकर दूर गिरे

बालोद,09 मई 2026। छत्तीसगढ़ के बालोद में तेज रफ्तार कार (CG 04 QB 5621) और बाइक की आमने-सामने टक्कर में 3 दोस्तों की मौत हो गई है। हादसे में एक का पैर कटकर अलग हो गया, दूसरे का हाथ कटा और तीसरे का पैर टूट गया है। बाइक सवार तीनों युवक के शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए। कार और बाइक के भी परखच्चे उड़ गए। मृतकों की पहचान सिर्राभाठा निवासी तरुण यादव (20), राहुल सेवता (20) और नरेंद्र भुआर्या (21) निवासी मुड़खुसरा के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। घटना डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र के खैरीडीह गांव की है। सिर्राभाठा निवासी तरुण यादव अपने दोस्त राहुल और नरेंद्र भुआर्य के साथ बाइक से डौंडीलोहारा जा रहे थे। इसी दौरान राजनांदगांव की ओर जा रही तेज

रफ्तार कार ने उन्हें सामने से जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार तीनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे में तरुण का हाथ शरीर से अलग हो गया, वहीं पीछे बैठे राहुल का पैर कटकर 50 मीटर दूर पैरावट में जा छिटका। नरेंद्र के शरीर पर भी गहरे जख्म थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां राहुल ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया, जबकि दो की मौके पर ही मौत हो गई थी। राहुल का कटा हुआ पैर आज (शनिवार) सुबह 8 बजे ग्रामीणों को मिला। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। डौंडीलोहारा टीआई सुनील तिर्की ने बताया कि, तेज रफ्तार और लापरवाही से यह हादसा हुआ है। युवक डौंडीलोहारा आ रहे थे। कार सवार दल्लीराजहरा से वापस राजनांदगांव लौट रहे थे। अभी कानूनी प्रक्रिया जारी है।

कोल लेवी घोटाला: सूर्यकांत के ड्राइवर की बेल खारिज

हाईकोर्ट बोला- ड्राइवर नहीं,वसूली नेटवर्क का एक्टिव मेंबर था,कारोबारी ने उसके नाम खरीदी संपत्ति

बिलासपुर,09 मई 2026। छत्तीसगढ़ कोल लेवी घोटाले के आरोपी और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के ड्राइवर की जमानत हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि नारायण साहू सिर्फ ड्राइवर नहीं, बल्कि पूरे वसूली नेटवर्क का एक्टिव मेंबर था, सूर्यकांत ने उसके नाम पर संपत्ति भी खरीदी है। बता दें कि, कोयला घोटाला केस में ईओडब्ल्यू आरोपी ड्राइवर की 2 साल से तलाश कर रही थी। उसे करीब दो महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। केस में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कोयला लेवी के पैसे के कलेक्शन और ट्रांसफर का भी काम करता था।

हाईकोर्ट में लगाई थी जमानत अर्जी

ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी के बाद उसे जेल दाखिल गया था, जिसके बाद आरोपी नारायण साहू ने ईडब्ल्यू की स्पेशल कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई, जिसे खारिज कर दी गई। इसके बाद उसने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। याचिका में उसने कहा कि ईओडब्ल्यू को उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। उसका कहना

है कि वह केवल कारोबारी का ड्राइवर था। कोयला घोटाले में उसका कोई हाथ नहीं है। उसने यह भी आरोप लगाया कि पहले उस पर खिलाफ में बयान देने के लिए दबाव बनाया गया। बाद में उसे फंसाने के लिए आरोपी बना दिया गया।

राज्य सरकार ने जमानत का किया विरोध : एजेंसियों के मुताबिक, इन दस्तावेजों से करोड़ों रुपए की अवैध वसूली के लेन-देन का लिंक सामने आया है। इसी आधार पर कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया आरोपी की भूमिका गंभीर है और उसे जमानत दिए जाने का आधार नहीं बनता। राज्य शासन की तरफ से कहा गया कि जांच में यह सामने आया कि नारायण साहू कथित कोल लेवी सिंडिकेट के जरिए करीब 13 करोड़ रुपए की नकद अवैध वसूली में शामिल था। आरोपी पिछले करीब ढाई साल से फरार चल रहा था। एजेंसी की पूछताछ से लगातार बचने की कोशिश कर रहा था। साथ ही जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। इस मामले में पहले ही कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।

हाईकोर्ट ने माना -एजेंसी के पास पर्याप्त सबूत

इस मामले में सभी पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने माना कि नारायण साहू सिर्फ ड्राइवर नहीं, बल्कि पूरे वसूली नेटवर्क का एक्टिव मेंबर था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में माना कि जांच एजेंसियों को नारायण साहू के खिलाफ गंभीर और ठोस सबूत मिले हैं। कोर्ट के अनुसार, नारायण साहू सूर्यकांत तिवारी का भरोसेमंद व्यक्ति था और कथित अवैध वसूली तंत्र में अहम भूमिका निभा रहा था। जांच के दौरान जब्त की गई हैंड रिटन डायरी में भी नारायण साहू के नाम से कई एंट्रियां मिलने का दावा किया गया है।

12-13 मई को आयोजित होगी छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक

रायपुर,09 मई 2026। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक बुलाई गई है। यह बैठक राजधानी रायपुर में 12 और 13 मई को आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी, जिला अध्यक्ष, कोर ग्रुप की बैठक होगी। इसकी जानकारी वन मंत्री केदार कश्यप ने दी है। वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि इस बैठक में संगठन के मंडल जिला प्रशिक्षण वर्ग की समीक्षा के साथ ही आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा भी तय की जाएगी। वहीं उन्होंने आगे बताया कि पार्टी इसमें एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित करेगी, जिसमें बंगाल, असम चुनाव में भाजपा की जीत पर मतदाताओं के साथ पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया जाएगा।

नगरीय प्रशासन विभाग में इंजीनियरों का हुआ तबादला..रायपुर-बिलासपुर समेत कई शहरों के अधिकारी बदले

रायपुर,09 मई 2026। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ इंजीनियरों के तबादला आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत राज्य के विभिन्न निकायों में पदस्थ कार्यपालन और सहायक अभियंताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। राज्य शासन द्वारा जारी सूची के अनुसार, लाल महेंद्र प्रताप सिंह कार्यपालन अभियंता को नगर निगम रायपुर से नगर निगम बिलासपुर भेजा गया है। इसी प्रकार दिनेश नेताम कार्यपालन अभियंता को कवर्धा से स्थानांतरित कर संयुक्त संचालक कार्यालय दुर्ग में पदस्थ किया गया है। अभियंताओं की नई पदस्थापना में बृजेश श्रीवास्तव सहायक अभियंता को कोण्डागांव से बिलासपुर और ललित कुमार त्रिवेदी सहायक अभियंता को भी बिलासपुर में प्रभारी कार्यपालन अभियंता की कमान सौंपी गई है। दुर्ग क्षेत्र में भी बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत सी.बी. परगनिहा सहायक अभियंता को दुर्ग से धमतरी, हेमन्त कुमार साहू सहायक अभियंता को भिलाई-चरौदा से नगर निगम दुर्ग और चन्द्रशेखर सारथी सहायक अभियंता को रायगढ़ से नगर पालिका चांपा भेजा गया है। वहीं नवा रायपुर में पदस्थ गगन वासन अब नगर निगम जगदलपुर में सहायक अभियंता के रूप में अपनी सेवाएं देंगे।

छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज...रायपुर समेत कई शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश

रायपुर,09 मई 2026। यूपी से ओडिशा तक बनी ट्रफ लाइन के असर से छत्तीसगढ़ में मौसम बदला हुआ है। शनिवार शाम रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। राजधानी के कई इलाकों में इस दौरान अंधेरा भी छाया रहा। भिलाई में आंधी तुफान के बाद छींटे पड़े। मौसम विभाग ने गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। प्रदेश में अगले 2 दिनों तक कुछ जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। हालांकि 11 मई के बाद आंधी-तूफान की गतिविधियों में धीरे-धीरे कमी आने के संकेत हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। शुक्रवार को प्रदेश का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में रिकॉर्ड किया गया।

डिजिटल अरेस्ट के नाम पर महिला से 1 करोड़ की ठगी

पुलिस-ईडी बनकर डराया,राजस्थान से 2 आरोपी गिरफ्तार...

बिलासपुर,09 मई 2026। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 1 करोड़ 4 लाख 80 हजार रुपए की साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के दो आरोपियों को रेंज साइबर थाना बिलासपुर की टीम ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर बिलासपुर लाया गया है। आरोपियों ने एक महिला को पुलिस, ईडी, आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का डर दिखाकर ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार पीड़िता के मोबाइल पर व्हाट्सऐप कॉल आया था, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को 'संजय पीएसआई' बताया। आरोपी ने महिला को कहा कि उनका नाम एक आतंकवादी संगठन से जुड़े मामले में सामने आया है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इसके बाद

वीडियो कॉल के जरिए महिला को घंटों तक तथाकथित 'डिजिटल अरेस्ट' में रखा गया। आरोपियों ने महिला को पुलिस, ईडी, आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट के नाम से फर्जी नोटिस और दस्तावेज भेजे। साथ ही परिवार से संपर्क करने पर बेटे और रिश्तेदारों को भी मामले में फंसाने की धमकी दी गई। लगातार मानसिक दबाव और डर के कारण महिला आरोपियों के झांसे में आ गई। आरोपियों ने अलग-अलग बैंक खातों में कई किश्तों में कुल 1 करोड़ 4 लाख 80 हजार रुपए ट्रांसफर करा लिए। इतना ही नहीं, केस खत्म कराने के नाम पर अतिरिक्त 50 लाख रुपए की मांग भी की जा रही थी। बाद में महिला ने अपने बेटे को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद साइबर थाना बिलासपुर में शिकायत दर्ज कराई गई। मामले की जांच के दौरान साइबर पुलिस ने बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल ट्रांजेक्शन की तकनीकी जांच की। जांच में सामने आया कि ठगी की रकम कई लेयर वाले बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी।

बैंकिंग ट्रेल और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने राजस्थान के चुरू जिले से दो आरोपियों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रूपेन्द्र सिंह (21) और विशाल सिंह (20) के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने कमीशन के लालच में अपने बैंक खाते उपलब्ध कराने और ठगी की रकम निकालकर अन्य लोगों तक पहुंचाने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बैंक पासबुक,चेकबुक,एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। मामले में अन्य आरोपियों और साइबर फ्रॉड नेटवर्क से जुड़े खातों की जांच जारी है।

रिश्वत लेते पकड़े गए पटवारी,कलेक्टर ने किया सस्पेंड...

दुर्ग,09 मई 2026। जिले में रिश्वतखोरी का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अहिवारा क्षेत्र के पटवारी लेकेश्वर सिंह ठाकुर को कलेक्टर अभिजीत सिंह ने निलंबित कर दिया है। आरोप है कि पटवारी ने जमीन बंटवारे के नाम पर एक बुजुर्ग महिला से 45 हजार रुपये की रिश्वत ली थी। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो में पटवारी पर पैसे लेने के आरोप लगाए गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए। तहसीलदार अहिवारा द्वारा की गई जांच में शिकायतकर्ता अमन कुमार टंडन और पटवारी दोनों के बयान दर्ज किए गए। जांच में सामने आया कि भूमि बंटवारे के काम के एवज में पटवारी ने 45 हजार रुपये लिए थे।

छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के जंगल से बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद

नारायणपुर,09 मई 2026। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ अंतर्गत कोहकामेटा थाना क्षेत्र के ग्राम टोके उपरपारा में बीएसएफ जवानों को जंगल में सर्चिंग के दौरान बंदूक,कारतूस और बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं। नारायणपुर पुलिस अधीक्षक ने इसकी पुष्टि की है। नारायणपुर पुलिस अधीक्षक रॉबिंसन गुड़िया ने शनिवार को इसकी पुष्टि करते हुए बताशा कि 135वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने डीमाइनिंग और सर्चिंग अभियान के दौरान सटीक खुफिया सूचना के आधार पर ग्राम टोके उपरपारा के घने जंगलों में शुक्रवार को सर्च ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में सुरक्षाबलों को बड़ी मात्रा में नक्सलियों का डंप बरामद हुआ है। बरामद सामग्री में .315 राइफल,

12 बोर राइफलें, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर,जिंदा कारतूस,3विस्फोटक सामग्री, डेटोनेटर, ट्रिगर मैकेनिज्म और संचार उपकरण बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अबूझमाड़ से नक्सलवाद के खात्मे के बाद नक्सलियों के छिपाकर रखे गये डंप को बरामद करने के लिए नारायणपुर के घने जंगलों में लगातार चलाए जा रहे अभियानों से नक्सली डंप बरामद करने में सफलता मिल रही है। बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।

पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सियासत टीएस के बाद अमरजीत आगे आए...

रायपुर,09 मई 2026। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। इसी बीच उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि यदि वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज हटे और उन्हें मौका मिला,तो वो भी पीसीसी चीफ बनना चाहते हैं। पीसीसी चीफ की लिस्ट में एक नाम उनका भी रहेगा, उनके इस बयान पर राजनीति भी तेज हो गई है। टीएस बाबा को पीसीसी चीफ बनाने के सवाल पर पूर्व केबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि टीएस बाबा हमारे राजा हैं, महाराजा हैं, राज परिवार ने सरगुजा में कांग्रेस को लम्बे समय तक साथ दिया है। अतिश्योक्ति नहीं है कि आदिवासी, सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग का नेता हो, पार्टी जिस पर मेहरबान

वह पहलवान है। उन्होंने आगे कहा कि सरगुजा और बस्तर आदिवासी सेंटर है, सरगुजा के आदिवासियो को भी साधने की व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि बीजेपी ने सरगुजा संभाग से आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है। कांग्रेस के फोकस में सरगुजा संभाग होना चाहिए, वरना गैप आएगा। सभी को साथ लेकर चले वैसा अध्यक्ष बनाना चाहिए। वहीं अमरजीत भगत से जब पूछा गया कि क्या आप अध्यक्ष बनेंगे तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अध्यक्ष बनने के लिए मैं कभी सोचा ही नहीं हूं।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)